[Shri Mukhtar Abbas Naqvi]

"That this House do appoint Shri Dilipbhai Pandya, Shri Shamsher Singh Manhas, Shri Pramod Tiwari, Shri A. Navaneethakrishnan, Shri Praful Patel, Shri Harivansh, Shri Satish Chandra Misra and Shri Sanjay Raut to the Select Committee to examine the Prevention of Corruption (Amendment) Bill, 2013, in the vacancies caused by the retirements of Shri Anil Madhav Dave, Dr. Chandan Mitra, Shri Avinash Pande, Shri A. Navaneethakrishnan, Shri K. C. Tyagi, Shri Satish Chandra Misra, Shri Praful Patel and Shri Sanjay Raut. This House also do appoint Shri Swapan Dasgupta to the said Select Committee in place of Shri Ramdas Athawale who has been inducted into the Union Council of Ministers."

The question was put and the motion was adopted

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall, now, take up the second motion by Shri Arun Jaitley.

MOTION FOR APPOINTMENT OF MEMBERS TO JOINT COMMITTEE ON ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST AND RECOVERY OF DEBTS LAWS AND MISCELLANEOUS PROVISIONS (AMENDMENT) BILL, 2016

THE MINISTER OF FINANCE AND THE MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRI ARUN JAITLEY): Sir, I beg to move:

"That this House concurs in the recommendation of the Lok Sabha that the Rajya Sabha do appoint three Members to the Joint Committee on Enforcement of Security Interest and Recovery of Debts Laws and Miscellaneous Provisions (Amendment) Bill, 2016, in the vacancies caused by the retirement of Shri Satish Chandra Misra, Shri Praful Patel and Shri K. C. Tyagi from the Rajya Sabha and communicate to the Lok Sabha the names of the Members so appointed by the Rajya Sabha to the Joint Committee and resolves that Shri Ramchandra Prasad Singh, Shri Satish Chandra Misra and Shri Praful Patel be appointed to the said Joint Committee to fill the vacancies."

The question was put and the motion was adopted.

GOVERNMENT BILLS

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall, now, take up the Child Labour (Prohibition and Regulation) Amendment Bill, 2012. Time allotted for this Bill is two-and-a-half hours. Shri Bandaru Dattatreya to move the Bill.

The Child Labour (Prohibition and Regulation) Amendment Bill, 2012

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT (SHRI BANDARU DATTATREYA): Sir, I beg to move:

> "That the Bill further to amend the Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986, be taken into consideration."

The question was proposed.

श्री शादी लाल बत्रा (हरियाणा): धन्यवाद महोदय। यह जो The Child Labour (Prohibition and Regulation) Amendment Bill, 2012 आया है, देखने में तो बहुत ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, लेकिन इनके हालात क्या हैं, हम चाहते क्या हैं? हम कहते हैं कि हमारे बच्चे कर्णधार हैं तथा कल के भविष्य के लिए वे ही हमारा फेस हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं तो बातों में कुछ सच्चाई नज़र नहीं आती। जिनको हम कर्णधार बतलाते हैं, वे बच्चे क्या कर रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? बच्चा पैदा होता है तो हर मां-बाप की इच्छा होती है कि मैं अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दूं, बड़े से बड़ा बनाऊं और वह समाज में तथा देश के लिए कुछ करे, लेकिन होता क्या है? आज अगर हम देखें तो हमारे 40 परसेंट देशवासी बी.पी.एल. कैटेगरी में हैं।

[**उपसभाध्यक्ष (श्री सुखेन्दु शेखर राय)** *पीठासीन हुए*]

बी.पी.एल. कैटेगरी में क्या होता है कि जब बच्चा पैदा होता है तथा जब बच्चे को स्कूल भेजने की बात करते हैं तो वे कहते हैं कि हम क्या करेंगे? गांव वाले कहते हैं कि हमारे मवेशी कौन ले जाएगा, उनको पानी कौन पिलायेगा तथा इस प्रकार से सौ काम होते हैं, खेती-बाड़ी के हों या मजदूरी के हों, वे सब काम करने पड़ते हैं। तो वे कहते हैं कि ये सब काम कैसे होंगे? वे बच्चों को कहते हैं कि कहीं और मत जाओ। अगर हमारा बच्चा मवेशियों को लेकर जाएगा, काम करेगा तो उसके लिए कुछ न कुछ ऐसा होगा कि हमारी बचत होगी और हम आगे चलेंगे। इस प्रकार उनका यहां से एम्प्लॉयमेंट शुरू होता है। वह ऍप्लॉयमेंट घर का हो, वह एम्प्लॉयमेंट बाहर का हो लेकिन एम्प्लॉयमेंट शुरू हो गया। एम्प्लॉयमेंट शुरू होने के बाद हम आगे चलते हैं तो फिर देखते हैं कि ऐसा होने के बाद कुछ और कार्य आगे नहीं हो रहा है। आज से दो साल पहले कांग्रेस गवर्नमेंट ने हरियाणा में किया था कि बच्चों को शिक्षा देने के लिए जब वे के.जी. में जाते थे तो शिक्षा फ्री होती थी तथा मिड-डे मील होता था। उसके साथ स्टाइपेंड भी दिया जाता था, ताकि वे पेरेंट्स जो बच्चों की कमाई पर चलना चाहते थे तथा अपने बच्चों की कमाई को आगे लेकर जाना चाहते थे, उनको हर महीने वह मिलता रहे। हम जब तक उन फैमिलीज़ को जिनके पास साधन नहीं हैं, जो अपने बच्चों पर निर्भर करते हैं कि वे कमाकर लाएंगे और सारा कुनबा खाएगा, तो जब तक उनके लिए कुछ साधन नहीं बनाएंगे तो बात नहीं बनेगी। शिक्षा नहीं होगी तो फिर क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट कैसे रोकेंगे, एम्प्लॉयमेंट में कैसे चलेंगे? आज अगर हम देखें तो हर साल साठ हजार बच्चे इस देश में गुम हो जाते हैं। जो बच्चे गुम होते हैं, वे किसलिए गुम होते हैं? इसलिए गुम होते हैं कि उनसे वेश्यावृत्ति कराई जाती है, उनसे भिक्षा मंगवाई जाती है, उनके शरीर के अंगों का व्यापार होता है। तो यह सब रोकने के लिए कानून-व्यवस्था क्या है? वह कानून-व्यवस्था कुछ नहीं है। कानून-व्यवस्था है नहीं, शिक्षा के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं

[श्री शादी लाल बत्रा]

तो फिर बच्चों का करेंगे क्या? बच्चे जो आगे आएंगे तो उनको कोई न कोई तो काम देना होगा, कुछ सोचना होगा और बच्चों को काम देने से पहले उनके माता-पिता को बताना होगा कि आने वाले भविष्य के लिए आपके बच्चे आगे क्या बनें, इसके लिए आप थोड़ा सोचिए और वे ऐसा तब सोच सकते हैं कि जब उनके पास कोई साधन हो।

उपसभाध्यक्ष जी, अगर हम बात करें तो एक बात तो क्लीअर हो जाती है कि हमने बहुत कानून बनाए। संविधान भी कहता है, बहुत अधिनियम भी हैं पर उन अधिनियमों को लागू कितना करते हैं? वे लागू नहीं होते। लागू नहीं होते तो सिर्फ कानून बनाने से बात नहीं बनेगी, आगे चलने से बात होगी कि हम कैसे करें और इसको कैसे बढ़ाएं। आज जो कानून आया है, एक रेग्युलेशन बिल आया है। इसमें एक सैक्शन 7 है, जिसमें परमिशन दे दी गई है कि बच्चों को अगर काम करना है, किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में जाना है तो उनका काम कितने घंटों का होगा, कितना रैस्ट होगा और क्या चीज होगी? इसका मतलब डबल परपज़ है। Section 7(1) says, "No child shall be required or permitted to work in any establishment in excess of such number of hours as may be prescribed for such establishment or class of establishments. (2) The period of work on each day shall be so fixed that no period shall exceed three hours and that no child shall work for more than three hours before he has had an interval for rest for at least one hour.

यह क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि हर आदमी यह चाहेगा कि जो बच्चा मेरे यहां काम कर रहा है, उसको एक रजिस्टर ही तो भरना होगा कि बच्चे ने तीन घंटे काम किया और उसको एक घंटे का रेस्ट दे दिया। इस तरह से वह काम कर रहा है। इससे क्या प्रभावित होगा? इससे उसकी शिक्षा प्रभावित होगी। इससे उसकी काम करने की भावना ऐसी बढ़ जाएगी कि उसको ऐसा लगेगा कि मैं काम करता रहूं। इसको अपने भविष्य के बारे में नहीं मालूम होता है कि मेरा भविष्य क्या है। उसको यह मालूम नहीं है कि आने वाले कल में क्या होगा, तो फिर हम इसको कैसे करेंगे? हम दोमुँही ज़बान बोल रहे हैं, एक तरफ तो रेग्युलेट कर रहे हैं कि चाइल्ड लेबर हो और दूसरी तरफ हम कहते हैं कि चाइल्ड लेबर न हो। चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए, मैं इस बात का हामी हूँ, लेकिन इसके साथ ही मैं आपसे एक और बात के लिए अनुरोध करना चाहता हूँ कि जहां हम शिक्षा अनिवार्य करते हैं कि हर बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए, तो इसके लिए ऐसे बीपीएल परिवारों के हर बच्चे को शिक्षा मिलने के लिए अगर हम के जी से लेकर ऊपर तक हर महीने stipend देंगे, तो हम उनको एक अच्छा नागरिक बना सकेंगे। इस तरह से अच्छा पढ़ा-लिखा व्यक्ति आगे आ जाएगा। हम किसी बच्चे को भिखारी नहीं बनाना चाहते हैं, हम उनके हाथ को इतना योग्य बनाना चाहते हैं कि वह काम करके आगे बढ़ सके, इसलिए उन्हें stipend दिया जाए।

महोदय, जो समस्याएं हैं, जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का सामना हम कैसे करेंगे? इसके लिए सबसे पहले गरीबी खत्म होनी चाहिए। इसके बाद शिक्षा के लिए हम इतने अच्छे स्कूल बना दें कि जो बच्चा उस स्कूल से पढ़ कर निकले, वह एक अच्छा नागरिक बन कर निकले। बच्चों के हाथ में किताबें होनी चाहिए, कलम होनी चाहिए, लेकिन आज क्या हो रहा है? आज उनके सिर पर ईंटें हैं, उनके हाथ में तलवार या कुल्हाड़ी है। जो बच्चा काम करने में लग जाता है,

4.00 P.M.

वह बच्चा पढ़ नहीं पाता है। यही कारण है कि हम अपने बच्चों को एक अच्छा नागरिक बनाने के बजाए एक मजदूर बना रहे हैं। एक अच्छा मजदूर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए और एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, इसके बारे में तो हमें सोचना होगा।

आज यह "बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2012" आया है, यह आज का बिल नहीं है, यह हमारे भविष्य को साधेगा। यह भविष्य का बिल है। इस बिल के माध्यम से हम अपनी जेनरेशन को, अपनी आने वाली पीढ़ी को, अपने आने वाली कौम को आगे ले जाने का काम करेंगे। हम उसको लेबर करने से रोकों, उसको शिक्षा दें। उसको इतना अच्छा नागरिक बनाएं कि वह ठीक ढंग से आगे बढ़ सके।

बच्चों की समुचित देखभाल और विकास पर भी हमारा ध्यान जाना चाहिए। देश को स्वतंत्र हुए 68 साल हो गए हैं, लेकिन बाल मजदूरी में निरंतर वृद्धि हो रही है, जो कि देश के विकास में बाधक बनती जा रही है। 25.2 करोड़ बच्चों में से 5 से 14 वर्ष की आयु समूह के 1 करोड़ 26 बच्चे बाल मजदूरी कर रहे हैं। इनमें से लगभग 12 लाख बच्चे खतरनाक व्यवसायों में कार्यरत हैं। इतनी संख्या में हमारे बच्चे बाल मजदूरी में लगे हुए हैं, तो उनसे हम क्या उम्मीद करेंगे? आखिर आतंकवाद कहां से शुरू होता है? आतंकवाद यहीं से शुरू हो जाता है। जब बच्चा इतना न कमा सके, जिससे वह अपना गुजारा कर सके, इतना न कमा सके कि अपने परिवार को पाल सके, इतना न कमा सके कि जो उसके ऊपर सामाजिक जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों को पूरा न कर सके, तो फिर क्या होगा? यही होगा कि वह आतंकवाद की ओर जाएगा। अगर हमें आतंकवाद से बचना है, भुखमरी से बचना है और इस व्यवसाय से बचना है, तो हमें इस तरह का काम करना होगा ताकि हम इससे बच सकें। हमें आने वाली पीढ़ी के लिए ऐसा वातावरण बनाना होगा, कुछ ऐसा सोचना होगा ताकि वे लोग अपने आप यह सोचें कि हम भी आज़ाद भारतवर्ष के बच्चे हैं और हमारा जो भी कर्तव्य है, हमसे जो भी आशाएँ की जा सकती हैं या हमसे जो भी अपेक्षाएँ हैं, उनको पूरा करने के लिए हम अपना कार्य करेंगे।

उपसभाध्यक्ष जी, वे अपना काम कब और कैसे पूरे करें, क्योंकि उनका काम बचपन से ही शुरू हो जाता है। ...(**समय की घंटी**)... अब हम देखें कि जो बच्चे 14 से 18 साल की आयु के हैं, उनको ऐसी किस इंडस्ट्री में काम करने के लिए जाना चाहिए, जो उनके लिए खतरनाक न हो? लेकिन बच्चे 7-8 वर्ष की आयु से ही काम करना शुरू कर देते हैं, तो 14 साल की आयु तक वे क्या करें? उस एज के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए सोचना होगा।

महोदय, यह जो बिल आ रहा है, जिसमें ये रेग्युलेशन कर रहे हैं और बच्चों को सर्विस दे रहे हैं, फिर यह कह रहे हैं कि तीन घंटे के बाद — इससे वे और भी बेईमानी की तरफ जाएँगे। फिर वे यह सोचेंगे कि इस क़ानून को हमें कैसे violate करना है। क़ानून बहुत-से हैं, क़ानूनों की कमी नहीं है, लेकिन वे लागू नहीं होते। जब वे लागू नहीं होते तो वे सोचते हैं कि इसके violation के लिए हमें यह करना है। मैं आज आपसे एक ही अनुरोध करना चाहूँगा कि हम जो भी सोचते हैं, वह इस दृष्टि से सोचते हैं कि हमें यह काम करना है, उसमें किसी प्रकार का कंसेशन देकर यह नहीं कहें कि इसको रेग्युलेट कर दें। अगर बच्चे की सर्विस लग जाती है, बच्चा काम करता है तो कोई बात नहीं, तीन घंटे काम करो। वह तीन घंटे काम नहीं करेगा तो हमेशा के लिए यह सोच लेगा कि मुझे नौकरी ही करनी है, मेरे लिए यही नौकरी बची है और फिर उसका बचपन

[श्री शादी लाल बत्रा]

खो जाएगा। जब उससे कोई गलती होती है, तो जहां वह काम कर रहा होता है, वहां के मालिक उसकी पिटाई करके उसको इतना डरा देते हैं, इतना धमका देते हैं कि वह बच्चा बिल्कुल सहम जाता है। यानी फिर वह बच्चा अपने जीवन में खुलकर आगे नहीं आ सकेगा, काम नहीं कर सकेगा, पढ़ाई नहीं कर सकेगा और वह सहमा-सहमा बच्चा अपना ही नहीं बल्कि अपने परिवार को भी आगे ले जाने के बजाय पीछे ले जाएगा। फिर वह कहीं न कहीं यह सोचेगा कि मैं वैसा काम करूँ। ...(**समय की घंटी**)... आज यह आम खबर आती है कि अगर कहीं पत्थर फेंकने हैं तो एक बच्चे को एक दिन के पांच रुपये भी मिल जाएँगे तो वह पत्थर फेंकेगा। अगर बच्चे पांच रुपये लेकर पत्थर फेंकते हैं, तो वह क्या है? उस बच्चे के जीवन के साथ क्या हो रहा है? उस बच्चे के जीवन को हम कितना exploit कर रहे हैं! इसलिए उस exploitation से बचने के लिए हम बच्चों को ऐसा कोई काम न करने दें जो असामाजिक हो, जो इल्लीगल हो, जो देश के हित में न हो। बच्चा ऐसा काम न कर सके , यह तब हो सकता है जब हम उसको पूरी शिक्षा देकर उसे ऐसा वातावरण दे दें, जिससे उसे लगे कि उसको एक अच्छा नागरिक बनकर देश की सेवा करनी है, परिवार की सेवा करनी है, अपनी सेवा करनी है, धन्यवाद।

डा. सत्यनारायण जटिया (मध्य प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष जी, बाल-श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2012 के बारे में हम यहां चर्चा कर रहे हैं। इसमें जो संशोधन किए जा रहे हैं, ये कोई नए नहीं हैं। इसके बारे में पहले ही चर्चा हुई है। जो काम करना चाहिए, जो काम पहले से प्रतीक्षित है, उस काम को अंजाम देने के लिए ही यह विधेयक हम लाए हैं। यदि हम इसके उदेश्यों के बारे में बात करेंगे तो निश्चित रूप से बालक श्रम अधिनियम, 1986 कुछ नियोजनों में बालकों को लगाए जाने का प्रतिषेध करने और कुछ अन्य नियोजनों में बालकों के काम की परिस्थिति का विनियमन करने का उपबंध करता है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को भी काम में नहीं लगाना चाहिए, यह बात मुख्यतया इस मान्यता के आधार पर है कि यह जो उम्र है, इस उम्र में बच्चों को पढ़ना चाहिए, शिक्षण करना चाहिए। देश के भविष्य का निर्माण करने के लिए यह जो बाल-शिक्षा है, यह बहुत जरूरी है।

परिस्थितियों के कारण, जब घर में रोजगार नहीं होता है, घर में गुजारे लायक और कोई कारोबार नहीं होता है, जब उसके मां-बाप रोजगार की तलाश में उस अनिश्चितता में बाहर निकलते हैं, तो बच्चे भी उनके साथ जाते हैं। गांव में रोजगार के अवसर बहुत कम हो गए हैं, क्योंकि कृषि का रकबा कम होता चला जा रहा है। उसके कारण किसानों का गुजारा नहीं हो पा रहा है और जो छोटे किसान हैं, उनकी स्थित बहुत खराब है। उनके पास बराबर रकबा नहीं होता है, तो उनको मजदूरी करनी ही होती है। ऐसे समय में बच्चे अपने मां-बाप के काम में हाथ बँटाने के लिए या तो अपने खेतों में काम करने के लिए जाते हैं या फिर वे वहां जाते हैं, जहां उनको काम मिलता है, चाहे वह शहर में मिले, पास के किसी और गाँव में मिले या किसी योजना के अंतर्गत मिले। फिर उस बच्चे को पढ़ने का जो मौका मिलना चाहिए था, उससे वह महरुम हो जाता है, उससे वह वंचित हो जाता है, क्योंकि वह मौका उसे नहीं मिलता है।

नियम यह कहता है कि जो बच्चा नहीं पढ़ता है या जो बच्चा काम पर नहीं जाता है या जो बच्चा पढ़ता है, पढ़ने के बाद भी अपने घर के कामकाज में हाथ बंटाने के लिए उसको इजाज़त मिलनी चाहिए। घर के कामकाज में हाथ बंटाने की इजाज़त मिलनी चाहिए, इसमें किसी को मनाही

नहीं है क्योंकि वह वहां पर कुछ सीखता है। वहां पर वह परम्परागत रूप से अपने उस रोजगार को तो सीख ही लेता है, जिस काम को वह अपने मां-बाप को करते हुए देखता है किन्तु वह काम, जिसे हम outsourcing कहते हैं, बाहर से काम लाना और बच्चों के माध्यम से उसे पूरा करवाना, वह ठीक नहीं है। इसके कारण उसका जो शिक्षा का समय होता है, सीखने का समय होता है, उसको यदि कमाने के समय में परिवर्तित कर दिया जाता है, तो बच्चों का विकास रुक जाता है। इस कानून में यह कहा गया है कि हां, ऐसे बच्चों के लिए, जो उनके परिवार के लिए कुछ काम कर रहे हैं, उनके लिए कुछ व्यवस्था बनानी चाहिए और उस व्यवस्था में कहा है कि कलेक्टर के अंतर्गत निरीक्षण की कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, जिसमें, ऐसे कामों में यदि कोई उन्हें बेवजह लगाता है या ऐसे कामों को, जिन्हें उन्हें नहीं करना चाहिए, उनमें लगाया गया है, तो उसके लिए सजा का प्रावधान होगा। पहले उसमें 3 महीने से लेकर 1 वर्ष का प्रावधान था, अब उसे बढ़ाकर 6 महीने से लेकर 2 वर्ष तक करने के बारे में कहा गया है।

महोदय, व्यावहारिक स्थिति यह है कि ऐसे बच्चों की तलाश करके उन्हें निकालकर लाने, उनका पुनर्वास करने और उनके लिए जो चाईड लेबर प्रोजेक्ट्स बनाए गए है, उन चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट्स में उनके शिक्षण के काम करने के लिए जो प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं, वे भी बहुत थोड़े हैं, कहीं-कहीं तो बंद हो रहे हैं। मुझे यह मालूम है कि जहां-जहां ये थोड़े-बहुत चल रहे होंगे, उन्हें भी कहा जा रहा है कि बालश्रम जो है, वह हमारे समाज के लिए कलंक है, अपराध है और ऐसा नहीं होना चाहिए। आईएलओ की रिपोर्ट के अनुसार इस सारे काम में सजग होकर, उनके convention को ध्यान में रखते हुए इसके बारे में हम चिंता करने का काम करते हैं। स्थिति यह हो गयी है कि चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं, उसके अंदर चलने वाले जो बाल विद्यालय हैं, उन बाल विद्यालयों के बारे में जो स्पष्ट घोषणा करनी चाहिए, वह करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त जो चल रहे हैं, वे ठीक प्रकार से कैसे चलें क्योंकि इन्हें चलाने के लिए राज्य सरकारें तैयार नहीं होती हैं और ये प्रोजेक्ट्स होते केंद्र सरकार के हैं। इस प्रकार परस्पर समन्वय के अभाव में ये सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं, वे कहीं चलते हैं, कहीं नहीं चलते हैं। इनकी स्थिति में सुधार करने के लिए उपाय करने चाहिए। मेरा यह कहना है कि ऐसे सारे कामों में, जहां प्रशिक्षण देना हो, शिक्षा के अलावा बच्चों को कुछ सिखाने का काम हो, इस प्रकार के कामों में उन प्रोजेक्ट्स को लगाने के संबंध में हमें उपाय करने होंगे। ये प्रावधान बनाए गए हैं कि ऐसे कामों को अगर कोई भी नियोजित करेगा, उनके खिलाफ दंडनीय कार्यवाही की जाएगी। ऐसे कामों के निरीक्षण भी होते हैं।

कुल मिलाकर, यह जो शिक्षा का काम है, जो प्रशिक्षण का काम है, इसमें तीन मंत्रालय सम्मिलित हैं। एक मानव संसाधन मंत्रालय है, जो सर्व शिक्षा अभियान की बात करता है। सर्व शिक्षा अभियान में जो उपाय हमें करने चाहिए, उन्हें करने के लिए हम बच्चों को गांवों से लेकर एक स्थान पर आते हैं और उनके शिक्षण की व्यवस्था करते हैं, उनके लिए छात्रावास बनाते हैं, छात्रावास की व्यवस्था करते हैं। इस काम को करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसके लिए पर्याप्त संसाधन न होने के कारण इसमें मुश्किलें आ रही हैं — यह हमारा प्रत्यक्ष अनुभव है। इसी प्रकार यह जो सर्व शिक्षा अभियान है, वह महिला और बाल कल्याण मंत्रालय है, उसमें भी आंगनवाड़ी और बाकी चीज़ें है, उनसे भी संबंध रखता है। तीसरा मंत्रालय, श्रम मंत्रालय भी इससे संबंध रखता है। इस प्रकार इन तीनों मंत्रालयों को साथ बैठकर एक ऐसी योजना बनानी

[डा. सत्यनारायण जटिया]

चाहिए, जिससे हम जो बाल शिक्षा के बारे में चिंता करना चाहते हैं, उनके प्रशिक्षण की बात करना चाहते हैं, उनके भविष्य की बात करना चाहते हैं, वह हो सके। बच्चे राष्ट्र का भविष्य हैं, यह कहने में अच्छा लगता है, बच्चों को काम नहीं करना चाहिए, यह भी अच्छा लगता है, बालश्रम नहीं होना चाहिए, यह कहना भी अच्छा लगता है, लेकिन उसके पीछे की जो परिस्थितियां हैं, जो गरीबी है, जो परेशानी है, परिवार की जो मुश्किलें हैं और देश में राजनैतिक तौर पर हम जो कहते रहते हैं कि हम गरीबी हटाएंगे, कुछ अच्छा समय लेकर आएंगे और उनके लिए कुछ काम करेंगे — यह बात अलग है कि इस सरकार के आने के बाद से हमने इस संबंध में कुछ अच्छे उपाय करने की कोशिश की है।

हमने लोगों की बेहतरी के लिए जन-धन योजना, मुद्रा योजना लाकर रोजगार को स्थापित करने का काम किया है, परन्तु अभी यह प्रारम्भिक अवस्था है। ऐसी अवस्था में ये दोनों बातें साथ-साथ चलाने के लिए जरूरी है कि जब तक इन सारे कामों से हम गरीबों को रोजगार देने का काम नहीं कर लेते तब तक बाकी की जो योजनाएं चली हुई हैं, उनको अच्छी प्रकार से चलाने का काम करें। यह जो संशोधन इस विधेयक का लाया गया है, यह तो बहुत प्रतीक्षित था। निश्चित रूप से यह एक पहल है कि किस तरह से हम बाल श्रम को बाकी के कामों से वंचित कर सकें। हैजार्डस कामों के बारे में कहा गया है। हैजार्डस काम तो फैक्टरी ऐक्ट के अंतर्गत आते हैं। बहुत सारे प्रोसेसेज़ बताए गए हैं, उनमें उनसे काम नहीं करवाना चाहिए। जो मजदूर होटल में काम करता है, वह लोगों के घरों में काम करता है, वह किस प्रकार की परिस्थितियों में काम करता है, इन सारी बातों की भी एक अलग से सूची बनायी जानी चाहिए। फैक्टरी ऐक्ट के अंतर्गत जिन कामों को हमने खतरनाक कहा है, उसकी सूची को पुनः बनाने का काम करना चाहिए। उसमें ऐसे कामों को समाहित करना चाहिए जो व्यावहारिक हैं। मौटे तौर पर यह जो बिल लाया गया है, इसका मैं समर्थन करते हुए यह उम्मीद करता हूं कि इसमें जो सुधार करने की गुंजाइश है, उसे तीनों मंत्रालय साथ में बैठकर करेंगे। हमारा जो लेबर मंत्रालय है और जो ट्रेड यूनियन्स हैं, मैं भारतीय मजदूर संगठन में वर्षों से काम करता आया हूं, मुझे मजदूर आंदोलन से जुड़े हुए 50 साल हो गए हैं। मैंने श्रम मंत्री रहते हुए भी ट्रेड यूनियन्स से बातचीत करके काम किया था। हम ILO में जाकर भी इस प्रकार की कन्वेंशन्स को पारित करने का काम करते हैं, हम डीसेंट वर्क की बात करते हैं। ये सारी बातें कांसेप्ट में तो बहुत अच्छी दिखाई देती हैं, लेकिन उनको व्यवहार में लाने के लिए हमें कारगर उपाय करने होंगे। अभी जो शुरूआत की है, उसका मैं स्वागत और अभिनंदन करते हुए अनुरोध करूंगा कि एक ऐसी समिति बनाएं कि आगे आने वाले समय में बाल श्रम को प्रतिषेध करने के लिए और बाल शिक्षा को बढ़ाने के लिए अधिक कारगर उपाय कर सकें, धन्यवाद।

श्री रवि प्रकाश वर्मा (उत्तर प्रदेश): सर, आज बड़ी उम्मीदों से लोग देख रहे थे कि आज हिन्दुस्तान की पार्लियामेंट में क्या होने वाला है। सर, मैं भी बहुत परेशान हूं। मैं कई बार कह चुका हूं कि हिन्दुस्तान में गरीबी, लाचारी, मजबूरी और बदहाली की उम्र कितनी होगी। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता था कि आज आप चाइल्ड लेबर पर अमेंडमेंट ला रहे हैं और खासतौर से 14 से 18 साल तक के बच्चों को eligible कर रहे हैं कि वे फैमिली के enterprise में काम करेंगे। फैमिली का जो enterprise है, उसका जो डायमेंशन है, उसका जो असर दिखाई पड़ रहा है, मुझे लगता है कि सरकार ने उसके ऊपर गौर नहीं किया है।

सर, हमें कभी-कभी लगता था.. जब से हमने भाग्य सीख लिया। अभी हमारे पूर्व मंत्री जी बता रहे थे कि सरकार बहुत कुछ कर रही है। क्या करेंगे जब लोगों का भाग्य ही खराब होगा! हिन्दुस्तान में तो भाग्य बहुत चलता है। अगर कुछ नहीं हो पाया, तो भाग्य के सहारे! हिन्दुस्तान की आजादी को 70 साल हो गए हैं — लाचारी, गरीबी, मजबूरी, बदहाली और बच्चों के साथ शोषण कि यह हमारी सामाजिक परम्परा है। यह बड़े शर्म की बात है कि हिन्दुस्तान के अंदर बच्चों से मजदूरी कराने में किसी को शर्म नहीं आती। यह लोगों की डिमांड है कि बच्चों के रूप में नौकर चाहिए। हमारी सरकार पीसमील में काम कर रही है, टुकड़ों-टुकड़ों में काम कर रही है। हिन्दुस्तान की जनता का दिल भर रही है। लोगों को दिखा रही है कि संसद बहुत काम कर रही है। इसका रिजल्ट क्या है, वही का वही है।

सर, हिन्दुस्तान में बच्चों के शोषण करने का सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर एक आर्गनाइज्ड सिस्टम है। इस आर्गनाइज्ड सिस्टम से लड़ने के लिए हमारे पास में इतना लचर कानून है, इतना कमजोर कानून है कि आज तक हम डिफाइन ही नहीं कर पाए कि चाइल्ड लेबर क्या बला है?

सर, दिल्ली हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया था कि चाइल्ड लेबर को डिफाइन करिए। चाइल्ड लेबर का टोटल elimination करने के लिए एक्शन प्लान बनाइए। सरकार एक काम कर रही है, पीसमील में काम कर रही है। सर, चाइल्ड लेबर का जो इश्यू है, यह कोई मामूली इश्यू नहीं है, यह पूरे हिन्दुस्तान में लोगों को प्रभावित करता है। सर, बड़े अफसोस की बात है कि इसी पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी जो सिफारिशें रखीं, उसमें साफ-साफ इस बात का उल्लेख किया कि जो प्रोविजन किए जा रहे हैं, सरकार जिस नीयत से, जिस मंशा से इसमें बदलाव ला रही है, वह ठीक नहीं है।

वे अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकते। सर, Ease of Doing Business के नाम पर, आर्थिक सुधारों के नाम पर, हमने इस देश की व्यवस्था को और संसाधनों को बाहर वालों के हवाले कर दिया और हम बहुत खुश हैं। मेहरबानी करके रहम करिए, माननीय मंत्री जी, रहम करिए। यह सरकार हिन्दुस्तान के बच्चों पर रहम करे, इन बच्चों को भाग्य के सहारे न करें, यह आपकी जिम्मेदारी है। आखिर एक बच्चा लेबर कैसे बन जाता है? मैं पहले भी कह चुका हूं कि जिन बच्चों को स्कूल में होना चाहिए, जिन बच्चों को मानव संसाधन के तौर पर विकसित करना है, हमें इस जिम्मेदारी को महसूस करना चाहिए। आज वे बच्चे मजदूरी कर रहे हैं और हम यहां बैठकर तसल्लीजनक तरीके से चर्चा कर रहे हैं।

सर, यह सिर्फ चर्चा का विषय नहीं है। यह तो एक समग्र क्रांति का विषय है। मैं माननीय मंत्री जी को और सरकार को बता देना चाहता हूं कि इस हिन्दुस्तान में स्टेट्समैन बनने का रास्ता खुले बाजार के रास्ते से नहीं है। स्टेट्समैन बनने का रास्ता WTO के माध्यम से भी नहीं है, यह रास्ता अमरीका से युद्ध संधि करके भी नहीं है। वह बच्चों के दिल में राज करके आगे बढ़ने का रास्ता है। हमने अभी कुछ समय पहले देखा, जब हमारे पूर्व राष्ट्रपति जिनका निधन हुआ, उनके निधन की बात सुनकर पूरा राष्ट्र स्तब्ध रह गया। हिन्दुस्तान का हर बच्चा, चाहे वह किसी भी कौम का था, किसी भी मजहब का था, उसके दिल में चोट थी। आज हमें यह रास्ता दिखाई पड़ गया कि हिन्दुस्तान में कैसे स्टेट्समैन पैदा किया जाता है। आज हम सरकार से इस बात का आग्रह करते हैं कि वह बच्चों के दिलों में झांक कर देखे। वे 22 करोड़ बच्चे, जो

[श्री रवि प्रकाश वर्मा]

प्राइमरी स्कूलों में हैं और इतने ही बच्चे, जो इससे ऊपर के स्कूलों में हैं, आज वे आपसे क्या चाहते हैं? वे आपकी तरफ किस लिए देख रहे हैं? आज आप उनके साथ क्या करने जा रहे हैं? हम पूरे तौर पर कह देना चाहते हैं कि आपने बच्चों के बीच में जो 14 से 18 का डिविज़न कर दिया है, यह न्यायसंगत नहीं है। ILO Convention साफ-साफ कहता है कि किसी भी हाल में हम पूरी धरती के बच्चों को ऐसे कारोबार के हवाले नहीं कर सकते, जहां उनका शारीरिक, मानसिक और नैतिक शोषण होता है या उनका पराभव होता है, लेकिन आज हम कानून में amendment करने जा रहे हैं, यह बात हमारी समझ में नहीं आ रही है।

सर, 1975 में इसी संसद ने यह तय किया था कि हमारे हिन्दुस्तान के बच्चे सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संसाधन हैं। आज कहां गया वह संकल्प, किस रास्ते चला गया वह संकल्प, आज क्यों भूल गए उस संकल्प को? हम आपको याद दिला देना चाहते हैं कि हिन्दुस्तान के बच्चों के साथ ऐसा धोखा मत करिए। यदि आप ऐसा धोखा करेंगे, तो आपको इसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। सच्चाई तो यह है कि 1987 में National Policy on Child Labour बनी, वह क्या कह रही थी, हम कहां पहुंचे? 2002 में Constitutional Amendment हुआ और Article 21A में शिक्षा का अधिकार दिया गया। सर, 2006 में prohibition on child labour as domestic workers or servants एचीव किया गया। उसके बावजूद भी 2011 की Census में आपको मालूम है कि कितने बच्चे child labour थे। जब हम सरकार की बात सुनते हैं, तो हमें कभी-कभी लगता है कि नौकरशाही बोल रही है, यह कोई जनता का नेता नहीं बोल रहा है। आपको तय करना पड़ेगा कि आप हिन्दुस्तान की पब्लिक के साथ खड़े हैं या नौकरशाहों के साथ खड़े हैं? हिन्दुस्तान के नौकरशाहों की जो सीमाएं हैं, वे हिन्दुस्तान की सीमाएं नहीं बन सकतीं। मैं आपको इस बात से आगाह कर देना चाहता हूं। आप लोग जिस तरीके से इसको लेकर चल रहे हैं, यह समझ में आने लायक बात नहीं है।

सर, आखिर बच्चा बाल श्रम बनता कैसे है? यह तय हो गया था कि हर बच्चे को स्कूल में दाखिल होना है और यह adhoc system, यह सर्वशिक्षा अभियान का adhoc system हम लोग कई बार कह चुके हैं कि इस हिन्दुस्तान में एक रेग्युलर एजुकेशन सिस्टम बनकर क्यों नहीं आता? ...(**व्यवधान**)...

श्री हुसैन दलवई (महाराष्ट्र): सर, प्वाइंट ऑफ ऑर्डर। यहां मिनिस्टर कौन है? ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: यहां पर मंत्री जी हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री रवि प्रकाश वर्मा: सर, मैं आगाह कर देना चाहता हूं कि कहां पर चूक हुई है? जिस देश में आजादी के दस वर्षों के बाद भी हर व्यक्ति को शिक्षित हो जाना चाहिए था, वहां पर आज भी शिक्षा की स्थिति बहुत खराब है। हमारा यह दुर्भाग्य है कि हम आज भी अपने नन्हे बच्चों को जो शिक्षा दे रहे हैं, हम उसके लिए एक रेगुलर एजुकेशन सिस्टम नहीं बना पाए।

सर, एक ad hoc system के सहारे, सर्व शिक्षा अभियान के सहारे, हम उन्हें शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं और उसमें भी कहीं टीचर नहीं हैं, कहीं स्कूल नहीं हैं, कहीं किताबें नहीं हैं। फिर हम उन्हें टीचर भी नहीं दे रहे हैं। दुर्भाग्य यह है कि हम उन्हें teaching servants के हवाले कर रहे हैं, जिन्हें बच्चों को पढ़ाने में मन नहीं लगता है। सर, ड्रॉपआउट्स का यही कारण

है। आज जितने बच्चे वहां enrolled हैं, literally उसके 50 प्रतिशत ड्रॉपआउट्स हैं। आपके पास आंकड़ा है कि सेंसस के मुताबिक हमारे यहां 4.35 परसेंट चाइल्ड लेबर्स हैं, लेकिन समाज के बीच में रहने वाले गैर सरकारी संगठनों ने बताया है कि ऐसे बच्चों की तादाद 11 मिलियन यानी 1 करोड़ से भी ज्यादा है। यह भी कोई छोटी संख्या नहीं है, लेकिन हमें समझ नहीं आता कि हम इतने ad hoc तरीके से काम क्यों कर रहे हैं? इस से कभी-कभी ऐसा लगता है कि सरकार ने कहीं Industrial lobby के सामने सरेंडर तो नहीं कर दिया है?

सर, देश में जितने चाइल्ड लेबर्स हैं, उतने ही नौजवान बेरोजगार हैं। आज वह बच्चा बेरोजगार व दिशाहीन सड़कों पर घूम रहा है, जिसके पास कोई लक्ष्य नहीं है। हमारे यहां कहा जा रहा था कि आज हिन्दुस्तान एक demographic dividend के मुहाने पर खड़ा है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि हम एक demographic disaster के मुहाने पर खड़े हैं। आपका फर्ज बनता था कि हम हर हाल में बच्चों को शिक्षित करते और उन्हें अच्छा नागरिक बनाते, लेकिन आज सब से बड़ी दिक्कत यह है कि जो बच्चा नौकरी के लिए जाता है, वह दूर से देखता है कि कुछ लोग अच्छे घरों में पैदा हुए, अच्छे स्कूलों में पढ़े, उन्हें अच्छा खाने व पहनने को मिलता है और इज्जत मिलती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपके दो बच्चे हैं तो मेहरबानी कर के एक को प्रिंस की तरह पालिए। उसे अच्छा खिलाइए, पिलाइए और उसे प्यार व सम्मान दीजिए व दूसरे बच्चे को उन बच्चों की तरह पालिए जैसे हिन्दुस्तान के चाइल्ड लेबर पाले जाते हैं, तब आपको पता लगेगा कि 70 वर्षों में हिन्दुस्तान कहां पहुंच गया है और क्यों पहुंच गया है और उसका क्या समाधान है? मैं यही बताना चाहता हूं कि जिस तरह से piecemeal तरीके से हिन्दुस्तान में बच्चों के लिए काम किया जा रहा है, वह हिन्दुस्तान के भविष्य को खराब कर रहा है। इससे फायदा नहीं होगा।

आपने बच्चों में डिवीजन कर दिया है। पूरी दुनिया चाहती है कि 18 साल से नीचे का बच्चा काम न करे, शिक्षा प्राप्त कर अपना कैरियर बनाए और एक इज्जतदार जिन्दगी का सपना देखे, लेकिन आप बता रहे हैं कि बच्चा family enterprise में काम करेगा। मैं आपको आगाह करना चाहता हूं, अभी कुछ साल पहले दिल्ली में एक भयानक घटना घटी जिस में एक लड़की निर्भया के साथ दुर्व्यवहार हुआ। उस अपराध में जो सब से छोटा बच्चा था, जिसने उस लड़की पर सब से ज्यादा atrocities commit कीं, वह चाइल्ड लेबर था। वह family enterprise से चाइल्ड लेबर लगाया गया था। इस से चाइल्ड लेबर के शिकार बच्चों का जो मानिसक स्तर है, उसकी जो इतनी नैतिक क्षति हुई है, उसका आप अंदाज़ लगा सकते हैं। क्या आपको इसे assess करने में देर लग रही है? मैं कहूंगा कि आपको सच्चाई का रूबरू होकर सामना करना चाहिए और अपने सेल से बाहर निकल आना चाहिए।

सर, मैं बार-बार कहता रहा हूं कि जो लोग हिन्दुस्तान में गरीबी के इश्यू को address करना चाहते हैं, वे अपने आप को और राष्ट्र को भी धोखा दे रहे हैं। आज मुद्दा गरीबी नहीं बल्कि productivity है। आज की तारीख में जो भी हिन्दुस्तान में पैदा हो, चाहे वह किसी भी कौम में हो, चाहे किसी मज़हब या धर्म या जाति में हो, उसे पढ़-लिखकर world class human resource बनने और एक इज्जतदार जिन्दगी जीने का अधिकार मिलना चाहिए। आज जब हम गरीबों की बात करते हैं, तो यह गरीबी इस सिस्टम का खेल है। यह गरीबी हिन्दुस्तान में 1947 तक थी, यह 1950 तक थी तो गनीमत थी, 1950 के बाद जब देश में हमारा संविधान लागू हो गया, उसके

[श्री रवि प्रकाश वर्मा]

बाद अगर देश में गरीबी कायम है, तो उसके लिए सरकार गुनहगार है और सिस्टम गुनहगार है। हिन्दुस्तान का हर आदमी जो मेहनत कर के आगे बढ़ना चाहता है, अगर वह शिक्षित और हुनरमंद नहीं हुआ है, तो वह under-productive है। वह गरीब और लाचार मजदूर नहीं है। हम इसकी definition को कब बदलेंगे? आज बताया जा रहा है कि गरीबी के कारण बच्चों को नौकरी करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। सर, हम इस व्यवस्था पर भी सवाल उठाना चाहते हैं। आज हमारी परिस्थिति ऐसी क्यों बन गई कि हमारे यहां बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग गरीब हैं, जिनके बच्चों को मजदूरी करनी पड़ रही है? सरकार चाहती थी कि बच्चे स्कूल में हों, लेकिन बच्चे स्कूल में नहीं हैं। सारी सरकारी मशीनरी और सारी सरकारी व्यवस्थाएँ असफल हो रही हैं और बच्चा चाइल्ड लेबर बन रहा है। आज हम कंसेशन कर रहे हैं कि 14 से 18 साल के बच्चे को फैमिली इंटरप्राइज़ में काम करने का मौका देंगे। आप देख लीजिए, 80 परसेंट से भी ज्यादा वे बच्चे, जो चाइल्ड लेबर से रिट्रीव किए गए हैं, वे फैमिली मेम्बर्स के साथ ही ट्रैफिकिंग के शिकार हुए हैं। ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री सुखेन्दु शेखर राय): रवि प्रकाश जी खत्म कीजिए।

श्री रवि प्रकाश वर्मा: सर, मैं पांच मिनट में खत्म कर देना चाहता हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुखेन्दु शेखर राय): नहीं, नहीं, आपका समय खत्म हो गया है।

SHRI RAVI PRAKASH VERMA: Sir, the Government has to take cognisance of the system. सर, मैं अपनी पार्टी से अकेला मेम्बर बोल रहा हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY): I am sorry, your time is over.

श्री रवि प्रकाश वर्मा: सर, आपको मुझे मौका देना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सच्चाई तो यह है कि जो हैजार्डस इंस्ट्रीज़ हैं, आज उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत उन्हीं नन्हे बच्चों की है। मैं अभी कुछ दिनों पहले टी. वी. देख रहा था। यह हैरत की बात है कि 2016 में, दिल्ली के आसपास बहुत-सी ऐसी कैमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, जहां पर नन्हे-नन्हे बच्चों का प्रोक्योरमेंट किया जाता है। उनसे काम लिया जाता है। वे जानते हैं कि जो ये काम करने वाले हैं, वे बचेंगे नहीं। सर, मैं टी.वी. में देख रहा था कि किस तरीके से बच्चों को लाया जा रहा था, किस तरीके से उनसे काम लिया जा रहा था, कैसे उन हैजार्डस गैसेज़ के माध्यम से उनके लंग्स छलनी हुए जा रहे थे। जब वे मर जाते हैं, तो बच्चों को बतलाया जाता है कि वह मामा से मिलने चला गया है। It was really pathetic. पता नहीं, आपने देखा है कि नहीं देखा है, लेकिन आपको देखना चाहिए था कि हम अपने बच्चों के साथ कैसा सलूक कर रहे हैं। ...(**समय की घंटी**)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY): Please conclude.

श्री रवि प्रकाश वर्मा: हैजार्डस इंडस्ट्रीज की जो सूची बनाई है, प्लीज़ उसको रिवाइज़ कीजिए। आप प्लीज़ उसको रिवाइज़ कीजिए। हम इसके लिए जमीन से लेकर आसमान तक लड़ने को तैयार हैं कि हम आपको यह चेतावनी देना चाहते हैं कि आप, किसी भी हाल में 14 से 18 साल तक के बच्चों को काम पर लगाने का प्रयास मत कीजिएगा।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY): Thank you. Shri A. Navaneethakrishnan.

SHRI RAVI PRAKASH VERMA: Sir, only one minute. I am concluding, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY): No, no. I have already called Shri A. Navaneethakrishnan. ...(*Interruptions*)...

श्री रवि प्रकाश वर्माः उपसभाध्यक्ष जी, ट्रैफिकिंग एक इंडस्ट्री बनकर सामने आ गई है। **...(व्यवधान)...**

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY): No, no. ...(*Interruptions*)... Nothing will go on record.

श्री रवि प्रकाश वर्माः *

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY): Shri A. Navaneethakrishnan.

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN (Tamil Nadu): Thank you, hon. Vice-Chairman. I thank hon. Amma. Before entering into merits and demerits of The Child Labour (Prohibition and Regulation) Amendment Bill, 2012, I would humbly submit before the august House that in Tamil Nadu, because of the best efforts taken by hon. Chief Minister Amma, there is no child labour. It has been eradicated. I would further say that there is no adolescent labour in Tamil Nadu because of the efforts taken by the hon. Chief Minister. ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY): Please address the Chair.

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN: I want to record it. Because of the best efforts taken by hon. *Amma*, no child is suffering from any difficulties. Yesterday, the school children were invited by hon. *Amma* to her chamber and she distributed the sweets. She gave a very good piece of advice to them for their very good future. She is always working for the welfare of the children. She has given much attention to the school education. I would also like to make it very clear that she has ordered English-medium classes in Government Schools. It includes LKG and UKG. It is happening in Tamil Nadu. There cannot be any dispute about it. I am saying this because the constitutional goals have been fulfilled by hon. Chief Minister *Amma*.

I would like to draw the kind attention of this august House to Article 39(f) of the Constitution. It says, "that children are given opportunities and facilities to develop in a healthy manner and in conditions of freedom and dignity and that

* Not recorded.

childhood and youth are protected against exploitation and against moral and material abandonment." In Tamil Nadu, hon. Chief Minister *Amma* has provided bicycles, notebooks, laptops, etc. free of cost. Now, other States are copying her. So, she has taken right steps to protect the interests of the children as contemplated under Article 39(f). Further, I would like to draw the kind attention of the august House to Article 39(e). It says, "that the health and strength of workers, men and women, and the tender age of children are not abused and that citizens are not forced by economic necessity to enter avocations unsuited to their age or strength." So, in Tamil Nadu, no child labour is prevailing.

Sir, I would like to draw the kind attention of the House to the definition of 'child' as given in the amendment Bill. A child means a person who has not completed his fourteenth year of age or such age as may be specified in the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009, whichever is more. I humbly submit that the second part "or such age as may be specified in the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009, whichever is more" is inappropriate. It is not correct. It is a defective one because the Right of Children to Free and Compulsory Education Act says that child means a male or female child of the age of six to fourteen years. This is with regard to free and compulsory education. This definition itself is now defective because child means a male or female child of the age of six to fourteen years. Now, transgenders have been recognised by the Supreme Court of India as third gender. Now, it is not mentioned here. Suppose a transgender child is employed in hazardous employment or prohibited employment, then we cannot punish the person who is employing that transgender because the definition of child under the Right of Children to Free and Compulsory Education Act includes only a male or a female. But, this definition "a person who has not completed his fourteenth year of age" is a correct definition. So, the second part must be deleted. I very honestly and sincerely request the Government to delete this portion. Otherwise, if a transgender is employed, an employer cannot be convicted. So, that is why, I humbly request and urge the Central Government to make necessary amendment in the definition of 'child' in this amendment Bill.

Further, I would like to draw the kind attention of this august House to certain Articles of our Constitution which are, I think, very relevant for our discussion. I think, in a way, a complete approach has not been adopted by the Government to abolish child labour. That is why, I am troubling the hon. Vice-Chairman to seek permission to read the relevant provisions of the Constitution. Article 45 provides for early childhood care and education to children below the age of six years. It says, "The State shall endeavour to provide early childhood care and education for all children until they complete the age of six years." So, even the Right of Children

to Free and Compulsory Education Act is defective. It is not in consonance with Article 45 because it contemplates children of six to fourteen years age. As per this definition, a child means a male or female child of the age of 6-14 years whereas Article 45 contemplates that the State shall endeavour to provide early childhood care and education for all children until they complete the age of 14 years. So, from the birth onwards, the State must take care of it. That is neglected.

Then, I would like to draw the kind attention of this august House to the 40th Report of the Standing Committee on Labour. I may be permitted to read the relevant portions because this Report's findings are not incorporated in the Bill. At page 28, I quote: 'The Supreme Court, in its judgement in the case of M.C. Mehta, had observed that providing an alternative source of income to the family is a prerequisite for the eradication of child labour and that employment should be provided to an adult in the family in lieu of a child working in a factory or mine or any other hazardous workplace'. That is omitted.

Then, as per the Amendment Bill, the District Magistrate is conferred with powers to implement these provisions of this Act. But the Committee finds that the Bill is also silent in this regard. The Committee, therefore, recommends that Vigilance and Monitoring Committees headed by local MPs may be constituted to review the implementation of not only the Child Labour (Prohibition and Regulation) Act but also all the Labour Acts in their areas every three months.

There is one more point, Sir. Just one minute more.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY): One minute only.

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN: I would like to submit to this hon. House that because of the best efforts taken by hon. *Amma* and I repeat, because of the efforts taken by hon. Chief Minister *Amma*, the Survey by the Ministry of Human Resources Development found a significant dip in school dropouts in Tamil Nadu. Not only this, the State has also achieved 99.3 per cent school enrolment of 6-14 year olds in rural areas which makes it the highest in the country as per the Annual Status of Education Report. So, in Tamil Nadu, there is no child labour, thanks to hon. Chief Minister *Amma*. Thank you, Sir.

श्री विवेक गुप्ता (पश्चिमी बंगाल): थैंक्यू वाइस चेयरमैन सर। मैं कुछ बोलूं, उससे पहले मैं संविधान की दो धाराओं की तरफ मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सर, धारा नं. 24 है, 'Prohibition of Employment of Children in Factories' और धारा न. 23 बहुत इंटरेस्टिंग है, 'Prohibition of Trafficking in Human Beings and Forced Labour' सर, माइंड किया जाए, 'Forced Labour'.

[श्री विवेक गुप्ता]

सर, पहली बात तो यह है कि 18 साल के बच्चे को हम वोट नहीं देने देते, क्योंकि वह सही-गलत का फैसला नहीं कर सकता है और 18 साल से पहले हम उसको शादी करने नहीं देते, क्योंकि हमें लगता है कि उस समय तक उसकी मानसिक स्थिति शादी के लायक नहीं होती, तो फिर 18 साल से पहले हम उसको काम करने के लिए कैसे मजबूर करते हैं? सर, मुझे यह समझ में नहीं आता है कि 18 साल से पहले वह इस स्थिति में कैसे आ जाता है कि वह इस बात का फैसला कर सके कि मुझे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और वह काम hazardous है या नहीं है? सर, यह चॉयस तो उस बच्चे की होनी चाहिए, हम लोग चॉयस क्यों कर रहे हैं कि वह hazardous है या नहीं है?

सर, जैसे छोटी क्लासेज़ में बच्चे जब लैसन सीख नहीं सकते हैं, तो उनको लैसन बार-बार रिपीट करवाया जाता है, उसी तरह 2012 तक पिछली सरकार ने जो गलतियां की थीं, आपके माध्यम से मैं उस तरफ इस सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, शायद मंत्री जी उन गलतियों को सुधार दें। सर, पिछले साल मैंने इसी सब्जेक्ट पर एक स्पेशल मेंशन भी दिया था और उसमें मैंने सरकार को इस बारे में आगाह करने की चेष्टा भी की थी। सर, artist और family enterprise, इन दोनों को छूट दी गई है। मज़े की बात यह है कि जो hazardous industries हैं, वे family enterprise में ही exempt हो जाती हैं। उदाहरण के तौर पर carpet weaving का काम है, जिसमें कई बार बच्चों के हाथ में सुई तक घुस जाती है। बीड़ी बनाने का काम, घर का काम और agricultural work. सर, मैं agricultural work के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। Agricultural work को non-hazardous में रखा गया है, जबकि insecticides और pesticides spray करना agriculture का ही पार्ट है। हमारे देबूदा हैं, जो फॉर्मर आईएएस ऑफिसर हैं, आज उन्होंने मुझे एक मज़ेदार चीज़ बताई, जो मुझे भी नहीं पता थी। बच्चों को जब खेती-बाड़ी का काम करना पड़ता है, तो मिट्टी पाटने के लिए उनको मिट्टी में हाथ सानना पड़ता है और कितनी बार नदी में उतर कर काम करना पड़ता है। यह non-hazardous है, लेकिन इसमें कई बच्चे बह जाते हैं और कई बच्चे मिट्टी में दब कर मर जाते हैं, लेकिन यह non-hazardous में आता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान इस ओर भी आकर्षित हो।

सर, कानून होने के बावजूद भी 12 लाख बच्चे अभी हैज़ार्डस इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि इन 12 लाख बच्चों को तो हम नहीं बचा पा रहे हैं, यहां पर इंप्लीमेंटेशन हो नहीं पा रहा है, अगर इस कानून में और ढिलाई हो जाएगी, तो फिर इंप्लीमेंटेशन के कहीं और बारह न बज जाएं। हमारे ऊपर अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी भी हंस रही है, क्योंकि उन्होंने कई बार हमसे आग्रह किया है कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के कन्वेंशन नंबर 182 में जो है, जिसमें कि चाइल्ड लेबर को एलिमिनेट करने की बात कही है, उस पर न हम कोई रेटिफाइ कर रहे हैं और न कोई जवाब दे रहे हैं। मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि मंत्री जी इस पर भी कुछ रोशनी डालें, इस पर भी कुछ जवाब दें। मजे की एक बात और है, जैसा अभी नवनीत जी ने स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट नंबर 40 का कहा है, उसी रिपोर्ट में एक बड़ा मजेदार ऑब्जर्वेशन है कि यहां पर तो हम खाली चाइल्ड और एडोलसेंट कह रहे हैं, वहीं कहीं उसको जुविनाइल बोला गया है। इससे भी आश्चर्यजनक बात यह है कि हर अलग-अलग एक्ट में चाइल्ड को अलग-अलग डिफाइन किया गया है। कहीं उसकी उम्र 14 बताई जाती है, कहीं 16 बताई जाती है, कहीं 15 बताई जाती है। इसकी डेफिनेशन अलग-अलग है। मैं चाहूंगा कि इसी बिल के माध्यम से मंत्री जी चाइल्ड को एक डेफिनेशन में बांध दें।

सर, मंत्री जी जानते ही होंगे कि "राइट टू एजुकेशन" जैसे पॉजिटव स्टेप्स में बच्चों का जो चाइल्ड लेबर था, वह करीब-करीब 12.6 मिलियन से घटकर 4.3 मिलियन हो गया है। इस बिल में एक लास्ट प्रॉब्लम और बताना चाहूंगा कि सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन आजकल एक नयी टर्म आयी है। जब 1982 में यह एक्ट बनाया गया था, उस समय सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन क्या था, हम नहीं जानते थे। एडल्ट्स के लिए सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का कानून आ गया, लेकिन बच्चों के लिए इस बिल में कुछ नहीं है। अब यहां ये काम करेंगे, चाहे वे किसी फैमिली में करें या आर्टिस्ट के यहां करें, जहां पर भी करें, इनका भी सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है। इसका उनके लिए कोई प्रिवेंशन, कोई प्रावधान नहीं रखा गया।

सर, मेरे कुछ सुझाव हैं, जो मैं यहां पर रखना चाहूंगा। बच्चों को एज में न बांधें, बच्चों को स्कूल लीविंग तक का किया जाए कि जब तक वे स्कूल से पढ़कर न निकलें, उनको कोई काम न दिया जाए। मॉनिटरिंग के लिए डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट को कहा जा रहा है, मैं चाहूंगा कि लोकल एमपी, कम से कम उस इलाके से जो एमपी हैं, उनको उसमें रखा जाए, क्योंकि उस एरिया के लोगों को एक एमपी समझता है।

सर, हमारी दीदी का मानना है कि बच्चे कोमल फूल होते हैं, उनको पनपने का, खिलने का मौका मिलना चाहिए। इनको स्किल डेवलपमेंट दिया जाए, नौकरी कराने के बजाय उनको ट्रेनिंग दी जाए, ताकि वे भी फ्लरिश कर सकें। मैं बंगाल का कुछ एग्जाम्पल देना जरूरी समझता हूँ, ताकि यहां उसको कुछ समझ सकें। युनाइटेड नेशंस में हमारी दीदी ने एक प्रोग्राम लांच किया, उसका नाम "कन्याश्री" है। यह "कन्याश्री" क्या है? "कन्याश्री" यह था, हमारे यहां खासकर जो लड़कियां हैं, उनकी जल्दी शादी हो जाती है, जो एक आम सच्चाई है। इसको डिले करना बहुत जरूरी था। हम लोग चाहते थे कि वे पढ़ें, लिखें, अपना पूरा पोटेंशियल रियलाइज करें। अब हमारे यहां "कन्याश्री" करके एक स्कीम शुरू हुई है कि जब कोई 18 साल तक स्कूल में या अपनी पढ़ाई-लिखाई कर रही होगी, तो उसको एक लंपसम रुपया मिलेगा और तब तक उसको महीना भत्ता भी मिलेगा। इसका बहुत अच्छा असर यह आया है कि कई लड़कियों को जो सैक्रिफाइस कर दिया जाता था, जिनकी जल्दी शादी कर दी जाती थी, वह रूक गई हैं, वे बचा ली गई हैं और कम से कम अब वे अपना भविष्य खुद तय कर रही हैं। इसको युनाइटेड नेशंस ने एप्रीशिएट किया है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी एप्रीशिएट किया है। इसका कुछ असर "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" में भी देखने को मिलता है।

सर, "युवाश्री" एक और कार्यक्रम है। इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग कार्यक्रम हमारी दीदी ने लांच किया, इसका नाम है- *'Sabooj Sathi'*। सर, यह देखा गया था कि एक लड़की को या किसी बच्चे को स्कूल पहुंचने में औसतन 45 मिनट से एक घंटा लगता है। इसके कारण ज्यादातर बच्चे स्कूल छोड़ देते थे। तो इस एक घंटे के समय को कम कैसे किया जाए, इसके लिए दीदी ने ब्रेनचाइल्ड निकाला कि उन बच्चों को साइकिल दी गई। अब ये बच्चे दस मिनट से भी कम टाइम में स्कूल पहुंचते हैं और इनका स्कूल ड्रॉपआउट बंगाल में बहुत कम हो गया है। अगर इसको सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनली एडॉप्ट करे, तो बहुत बढ़िया हो सकता है। साथ में इनके सोशल डेवलपमेंट का भी ख्याल रखा जाए। सर, "अपराजिता" नाम से मालनरिश्ड बच्चों के लिए भी हम लोगों ने स्पेशल कार्यक्रम किया है और "अपराजिता" से डीडी-वन, दूरदर्शन में हम लोगों को अवेयरनेस दिला रहे हैं कि बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को काम पर न लगाओ। सर,

अंत में मैं बच्चों की आवाज में आपको संबोधन कर रहा हूँ—

जरा सा कम हूँ मैं, फिर भी नामुकम्मल हूँ मैं,
यहां मिले हैं मुझे सभी, मुझको टालने वाले।

धन्यवाद।

SHRIMATI JHARNA DAS BAIDYA (Tripura): Mr. Vice-Chairman, Sir, I rise to oppose the Child Labour (Prohibition and Regulation) Amendment Bill, 2012. We strongly oppose legalising child labour in "family enterprises". This is a retrograde measure which legalizes the exploitation of the labour of children below the age of 14. To suggest that "poverty and the social fabric of India" justify the use of child labour, I think, it will be to punish children for their poverty.

The Government's economic reforms promote 'outsourcing'. Many developed industries farm out work to contractors who further farm out work to families who work round the clock at exploitative rates. This is in addition to other trades such as bidi making, agarbattis, carpet weaving, etc., where children are forced to work. Since it is impossible to regulate "family enterprises" such an amendment will open the floodgates for the rampant use of child labour.

Coming as it does in the wake of the severe cuts in the budgetary allocations for children's development, the proposed amendment exposes the callous approach of this Government to children's rights.

The Employment Survey of 2013-14 (Volume 1) shows that only 52.5 per cent of the people above the age of 15 years are in the labour market, and of them, a majority *i.e.*, 51 per cent of men and 49.2 per cent of women workers are self-employed. About 29.3 per cent of men and 36.5 per cent of women are casual workers. Of the casual workers, only 42.9 per cent of the workers get 12 months of work, whereas more than half the casual workers and, at least, one fourth of the self employed workers do not get more than six months of employment. In this situation, the legalisation of child labour will only worsen the situation because it will induce the employment of children in place of able bodied adult workers. Hence it will create conditions for augmenting unemployment and increasing the labour reserve which will further depress wages.

We are opposing the Bill as we have many concerns. A household enterprise is nothing but an exit route to allow children to work. Also there is a need for rehabilitation of adolescent worker.

The International Labour Organisation (ILO) too had said that the clause needs to be further debated. The proviso is very crucial as not only education but also

health and welfare of children is important. But it is a clause that should be further debated. How do you monitor it? So the child labour law has to be set in that context.

The amendments to the Child Labour Act can also be seen as a part of this exercise and its implications for the labour market are yet to be properly analysed.

In reply to a question given in Parliament by the Ministry on 14th March, 2016 the main workers in the age group 5-14 years as per Census, 2011, are 43,53,247. And Uttar Pradesh has witnessed 13 per cent increase in child labour. With one out of every five child labour in India belonging to the State of U.P., the total number of child labour in the State is 8,69,301. Interestingly, more than half of the working children in India are concentrated in just five States, namely, Bihar, Uttar Pradesh, Rajasthan, Madhya Pradesh and Maharashtra. These States account for more than 55 lakh child workers. We feel the provisions on hazardous child labour have been diluted in this Amendment Bill of 2012.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY): Please conclude.

SHRIMATI JHARNA DAS BAIDYA: We demand total eradication of child labour up to the age of 18 years. No more regulation of child labour is required. It should be completely prohibited up to the age of 18 years. We want that the provision pertaining to a time-bound rehabilitation of child labour should be incorporated in the Act. We are against the practice of allowing children to work beyond school hours, or, allowing children to work in aid of their families or asking them to do home-based work. Our demand is that there should be a complete ban on any form of child labour, anywhere, and at any point of time.

श्रीमती सरोजिनी हेम्ब्रम (ओडिशा): माननीय उपसभाध्यक्ष जी, आज के माहौल में बच्चों को उनका अधिकार दिलाने तथा सुरक्षित रखने की दृष्टि से यह विधेयक अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुझे इस बिल के ऊपर बोलने का मौका देने के लिए मैं आभार प्रकट करती हूं। इस मौके पर अपनी पार्टी बीजू जनता दल और हमारे नेता, ओडिशा में माननीय मुख्य मंत्री श्री नवीन पटनायक जी का भी आभार प्रकट करना चाहती हूं कि उन्होंने मुझे संसद के उच्च सदन में ओडिशा का प्रतिनिधित्व करने और जनता की सेवा करने का अवसर दिया। महोदय, मेरे पिताजी श्री सी.पी. मांझी 1972 से 1978 तक इस सदन में सांसद रह चुके हैं और वे पैट्रोलियम और केमिकल मिनिस्टर भी रह चुके हैं और स्टेट में एस.सी., एस.टी. और एजुकेशन मिनिस्टर भी थे। उन्होंने विशेषकर आदिवासी महिला और दलित वर्ग तथा पिछड़े वर्ग के शैक्षिक विकास के लिए पूरी जिंदगी काम किया है, जिसने मुझे प्रभावित किया और उन्हीं की राह पर चलते हुए मैं भी पोलिटिक्स में आई। मैं स्टेट में एम.एल.ए. थी तथा हैण्डलूम टैक्सटाइल्स मिनिस्टर भी रह चुकी हूं। अभी इस उच्च सदन में फिर से जो मुझे मौका मिला जनता की सेवा के लिए और यहां उच्च सदन में आकर मुझे मेडन स्पीच बोलने का जो मौका मुझे बहुत अरसे के बाद मिला है, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY): Is it your maiden speech?

श्रीमती सरोजिनी हेम्ब्रमः महोदय, आज जिस विषय पर चर्चा हो रही है, चाइल्ड लेबर या बाल श्रमिक, केवल भारत में नहीं, बल्कि पूरे विश्व में एक चैलेंज की तरह उभरा है। लेकिन 2001 की जनगणना के हिसाब से भारत में सबसे ज्यादा बाल श्रमिक हैं। सर, गरीब और सामाजिक सुरक्षा की कमी बाल श्रम का प्रमुख कारण माना जाता है। 80 परसेंट बाल श्रमिक ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। हर चार में से तीन बच्चे अपने माता-पिता द्वारा कृषि क्षेत्र में पाए जाते हैं। 14 से 18 साल के अंदर के बीच 20 परसेंट बच्चे खतरनाक कामों में नियोजित होते हैं। तो भारत समेत विश्व में सभी विकासशील देशों में बाल मजदूरी का सबसे मुख्य कारण गरीबी, शिक्षा की कमी, अमीर और गरीब के फासले में वृद्धि और भुखमरी हैं। 5.5 मिलियन बाल श्रमिक, ज्यादातर बिहार, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में केंद्रित हैं।

महोदय, "बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2012" बिल राज्य सभा में दिसम्बर, 2012 में introduce हुआ था। इस बिल में यह प्रावधान है कि अगर एक बच्चा जिसकी उम्र 14 साल से कम है और एक किशोर जिसकी उम्र 14 साल और 18 साल के अंदर है, उनको शिक्षा अधिकार कानून, 2009 के तहत प्राथमिक शिक्षा दी जानी चाहिए, लेकिन आज तक उनको इसका फायदा ठीक तरह से नहीं मिला है।

सर, भारतवर्ष में प्रारंभ से ही बच्चों को भगवान का रूप माना जाता है, लेकिन आज की तस्वीर इससे बिल्कुल अलग है। बाल श्रम की वजह से बच्चों का भविष्य अंधकारमय होता जा रहा है। गरीब बच्चे सबसे ज्यादा शोषण के शिकार हो रहे हैं। बचपन हर एक के जीवन का सबसे खुशनुमा और जरूरी अनुभव माना जाता है, क्योंकि बचपन सीखने का बहुत जरूरी और दोस्ताना समय होता है। बच्चों को अपने माता-पिता से प्यार, परवरिश, स्कूल जाने, दोस्त के साथ खेलने का पूरा अधिकार होता है। बाल मजदूरी के कारण हर दिन न जाने कितने अनमोल बच्चों का जीवन बिगड़ रहा है। बाल श्रम मानव अधिकार का खुला उल्लंघन है। यह बच्चों के मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक और सामाजिक हितों को प्रभावित करता है। बच्चे आज के परिवेश में भी घरेलू नौकर का कार्य कर रहे हैं। वे होटल्स, कारखानों, बीड़ी फैक्ट्रियों, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन्स, पटाखे के कारखानों और दुकानों आदि में काम कर रहे हैं, जिससे उनका बचपन पूर्णतः प्रभावित हो रहा है।

महोदय, भारत के संविधान का अनुच्छेद 26 यह स्पष्ट करता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को ऐसे कारखानों इत्यादि में न रखा जाए, जो खतरनाक हों। कारखाना अधिनियम, बाल अधिनियम, बाल श्रम निरोधक अधिनियम आदि भी बच्चों के अधिकार को सुरक्षा देते हैं।

सरकार द्वारा बच्चों के उत्थान के लिए अनेक योजनाएं प्रारंभ की गई हैं, जिनसे बच्चों के जीवन और शिक्षा पर सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन बाल श्रम की समस्या फिर भी विकट समस्या के रूप में विराजमान है। कम उम्र के बच्चों से जिन कारखानों, फॉर्म्स, दुकानों आदि में काम कराए जा रहे हैं, उन सब जगहों पर ठीक तरह से छापा पड़े और उनके मालिकों या employer के विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बाल श्रम या बच्चे को नियोजित की जाने वाली जगहों पर रूटीन जांच होनी चाहिए। इसके लिए जिला में कलेक्टर और एसपी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जिन बच्चों को rescue किया जाता है, उनको ठीक तरह से educate करना चाहिए।

5.00 P.M.

जो पढ़ना चाहते हैं, वे तो पढ़ेंगे ही। हमारा मयूरभंज जिला है, वह बहुत बड़ा जिला है, उसमें 26 ब्लॉक्स हैं। वहां पर जिन बच्चों को rescue किया जाता है, उनको एक जगह रखा जाता है। वे लोग पढ़ाई भी करते हैं, लेकिन पढ़ाई के साथ-साथ उनको ठीक ढंग से vocational training या Skill Development के तहत ट्रेनिंग दी जाए, तो इससे उनको रोजगार मिलने में सुविधा होगी।

जो लोग बार-बार गलती कर रहे हैं, उनके लिए जुर्माने की राशि जो 10 हजार रुपए है, उसको और बढ़ाना चाहिए, क्योंकि नियम-कानून ठीक न होने से हम आज जो बिल ला रहे हैं, वह ठीक तरह से implement नहीं हो पाएगा। जो एनजीओज़ हैं, उनको और भी एक्टिव होकर इस दिशा में काम करना चाहिए।

महोदय, बिल में जो प्रावधान है, उसके अनुसार 14 साल के कम उम्र का बच्चा अगर स्कूल के बाद अपने परिवार के बिजनेस में हाथ बंटाता है, तो वह अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। इस प्रावधान के कारण चाइल्ड लेबर को रोकने में मुश्किल हो सकती है। उसी तरह, फिल्म या टीवी में काम करने वाले बच्चे भी शोषण का शिकार होते हैं, तो उन्हें छूट देते समय भी यह बात ध्यान में रखी जानी चाहिए थी। दूसरी बात यह है कि जिला स्तर पर चाइल्ड लेबर की मॉनिटरिंग कौन करेगा, यह महत्वपूर्ण बात है। मेरा सुझाव है कि स्थानीय एमपी को इसकी मॉनिटरिंग का अधिकार मिलना चाहिए। जहां तक खतरनाक उद्योग की परिभाषा का सवाल है तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की इस संबंध में काफी व्यापक परिभाषा है और हमें भी उस परिभाषा को अपनाना चाहिए। इस बिल में अच्छी बात यह है कि चाइल्ड लेबर से मुक्त कराए गए बच्चों के पुनर्वास के लिए फंड की व्यवस्था की गई है। साथ में, मैं यह कहना चाहूँगी कि चाइल्ड लेबर में भी अधिकांश वीकर सेक्शंस और दलित-आदिवासी बच्चे शामिल होते हैं, इसलिए पिछड़े समुदाय का विकास इससे बाधित होता है। चाइल्ड लेबरर्स हर प्रकार के शोषण का शिकार बनते हैं, इसलिए हमें न सिर्फ चाइल्ड लेबर का क़ानून बनाना होगा, बल्कि जमीन पर उनका सही ढंग से इम्प्लिमेंटेशन भी करना होगा, तभी जाकर सुधार आएगा।

हमारे ओडिशा के माननीय मुख्य मंत्री जी ने जन्म से लेकर मृत्यु तक की कई लोकप्रिय योजनाएँ बनाई हैं। शिशु और मां के लिए "ममता योजना" है, जिसमें गरीब घरों में शिशु के जन्म के बाद पांच हजार रुपये की चार किस्तों में सहायता दी जाती है। तीन साल से छः साल तक बच्चों के लिए "नुआ अरुणिमा योजना" है, जिसके तहत उनको प्राथमिक विद्यालय तक की शिक्षा दी जाती है। जो निर्माण-कार्य के समीप हैं, उनके बच्चों के लिए सहायता दी जाती है। मछुआरों के परिवारों और बच्चों के लिए 3,000 रुपये लेकर 7,500 रुपये तक की सहायता दी जाती है। गवर्नमेंट स्कूल्स और एडेड स्कूलों में पहली कक्षा से आठवीं कक्षा तक पढ़ने वाले बच्चों के लिए चार जोड़ी यूनिफॉर्म्स मुफ्त में दी जा रही हैं। "बालिका शिक्षा प्रोत्साहन कार्यक्रम" में नौवीं और दसवीं कक्षा तक पढ़ाई जारी रखने के लिए 3,200 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। सब-गवर्नमेंट, नॉन-गवर्नमेंट और एडेड हाई स्कूलों में जो लड़कियां दसवीं कक्षा में पढ़ाई कर रही हैं, उनको साइकिल दी जाती है। उनके अलावा, एससी, एसटी तथा बीपीएल परिवार के छात्रों को भी साइकलें दी जाती हैं। इसी कारण, उनका ड्रॉपआउट बहुत कम हुआ है। इसके अलावा, बच्चों और महिलाओं को जरूरत के समय तत्काल मदद के लिए "महिला और शिशु डेस्क" बनाया गया है। ओडिशा के सभी पुलिस थानों में "शिशु डेस्क" की स्थापना की गई है और महिला श्रमिकों को दो बेटियों तक की शादी में सहायता राशि के रूप में 5,000 रुपये दिए जाते हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY) : Excuse me. Excuse me for a second. Kindly listen to her. This is her maiden speech. Please listen to her. I appeal to everybody to please listen to her. ...(*Interruptions*)... Please continue. ...(*Interruptions*)... आप बोलिए।

श्रीमती सरोजिनी हेम्ब्रमः महोदय, इस अहम बिल के ऊपर मुझे बोलने का मौका दिया गया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करती हूँ और हमारे देश के बच्चों के भविष्य के लिए इस क़ानून को सख्त बनाने और इसको इस्तेमाल करने के लिए सरकार से विनती करती हूँ। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करती हूँ, धन्यवाद।

श्री राजाराम (उत्तर प्रदेश)ः उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2012 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारी पार्टी की नेता बहन सुश्री मायावती जी ने मुझे इस बहस में बहुजन समाज पार्टी का पक्ष रखने का मौका दिया, इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं।

महोदय, यह विधेयक बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह देश की भावी आशाओं या किशोर से जुड़ा हुआ है, जिसकी तादाद भारतवर्ष में करोड़ों में है। महोदय, बाल श्रम आधुनिक भारत निर्माण के लिए एक अभिशाप है। जहां हमें 1947 में आज़ादी हासिल हुई, वहीं आज भी हमारी कुल आबादी का एक बड़ा हिस्सा श्रम की गुलामी में फंसा हुआ है। यह एक तरह से आर्थिक गुलामी का प्रतीक है। अगर देखा जाए तो बाल श्रम में पाए जाने वाले अधिकांश बच्चे दलित समाज, आदिवासी समाज, पिछड़ी जातियों तथा अल्पसंख्यक समाज से ही आते हैं। इससे यह साबित होता है कि आज़ादी को प्राप्त हुए करीब 70 साल होने जा रहे हैं, लेकिन आज भी इस देश में समता मूलक समाज नहीं बन पाया है। जो पिछली सरकारें रही हैं, यह उन सरकारों की दलित, पिछड़ा, आदिवासी और अल्पसंख्यक विरोधी सोच को ही दर्शाता है।

महोदय, अगर इस विधेयक पर दी गयी स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट को पढ़ा जाए तो यह पता चलता है कि यह विधेयक आईएलओ के कन्वेंशन नं. 138 तथा 182 की तर्ज पर बनाया गया है। बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि आईएलओ का कन्वेंशन नं. 138 सन् 1973 में पारित हो गया था, यानी यह कन्वेंशन 43 सालों से हमारे यहां लम्बित है और कन्वेंशन नं. 182 सन् 1999 में आईएलओ ने पारित किया। दोनों कन्वेंशन बच्चों के मानवाधिकारों की बात करते हैं। भारत आईएलओ का शुरू से ही सदस्य रहा है, लेकिन भारत आज़ादी के बाद अब तक बच्चों का उत्पीड़न रोकने के लिए कोई ठोस कानून नहीं बना पाया। अगर कानून बनाया भी, तो भी उसमें कुछ कमियां रह गयीं, जिनकी वजह से आज भी यह कानून बेअसर साबित हो रहा है।

महोदय, अगर एशियन सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स के आंकड़ों को माना जाए, तो 2001 से 2011 के बीच, इन दस सालों में बच्चों से हो रहे बलात्कारों की जो एफआईआर दर्ज हुई हैं, उनकी संख्या 48,338 है। इन दस वर्षों में बलात्कार की जो घटनाएं बच्चों के साथ हुई हैं, इनमें 336 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह बहुत ही चिंता का विषय है। भारत का प्रत्येक चौथा बालक आज भी बाल श्रम के चलते स्कूल नहीं जाता है। 2001 की जनगणना के अनुसार 5 से 14 वर्ष की उम्र के 1 करोड़ 26 लाख बच्चे आज भी श्रम की हैसियत से काम करते हैं।

महोदय, आज भी जो कानून हम बना रहे हैं, वैसा कानून 1960 से पहले ही बन जाना

चाहिए था। अगर हमने बाबा साहेब डा. भीम राव अम्बेडकर जी के सुझावों पर पूरी तरह अमल कर लिया होता तो यह कानून पहले ही बन जाना चाहिए था। महोदय, चूंकि हमारे पास समय कम है इसलिए मेरे एक-दो सुझाव हैं, जो मैं आपके माध्यम से देना चाहता हूं।

इस विधेयक के अंतर्गत जो मॉनिटरिंग या नोडल अधिकारी बनाया गया है, वह जिला कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट को बनाया गया है। महोदय, उनके पास पहले ही बहुत काम है। अगर जिला कलेक्टर को नोडल अधिकारी बनाया जाता है तो मुझे लगता है कि उससे इसकी उचित मॉनिटरिंग नहीं हो पाएगी। इसलिए मेरा सुझाव है कि इसे किसी सरकारी या गैर सरकारी लोगों तथा जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, उनके अधिकार क्षेत्र में लाया जाए। यह सुचारू रूप से लागू हो रहा है, इसे देखने का काम इन लोगों को देना चाहिए। इस तरह की कमेटी बनानी चाहिए। ...(**समय की घंटी**)... महोदय, मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। मैंने कुछ बातों को छोड़ दिया है क्योंकि मैं जानता हूं कि आपकी बेल बजेगी।

अंत में, यह विधेयक हमारे बच्चों का उत्पीड़न रोकने के लिए तथा उनका भविष्य सुधारने के लिए एक महत्वपूर्ण विधेयक है। साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगा कि अगर हमें शोषित बच्चों का भविष्य सुधारना है तो हमें इन बच्चों की निःशुल्क शिक्षा और शिक्षा पूरी होने के बाद रोज़गार के उचित अवसर प्रदान करने होंगे। इस विधेयक को कारगर बनाने के लिए यह आवश्यक है कि जिन गरीब परिवारों के बच्चे आते हैं, उन परिवारों की आजीविका सुनिश्चित करायी जाए और उन्हें बेहतर रोज़गार के अवसर प्रदान किए जाएं, धन्यवाद।

(MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair*)

DR. NARENDRA JADHAV (Nominated): Mr. Vice-Chairman, Sir, thank you for giving me this opportunity. Several hon. Members have made emotionally charged interventions and I completely and wholeheartedly agree with the spirit in which hon. Members, especially Shri Ravi Prakash Verma, spoke here today. बाल मजदूरी यह हमारे देश के ऊपर कलंक है, इसमें कोई संदेह नहीं है।

Sir, I would like to make five observations on Child Labour (Prohibition and Regulation) Bill. My first observation is that this Bill is certainly a move in the right direction. If you look at the incidence of child labour, the Planning Commission's Twelfth Five Year Plan Document gives a time series of a broad picture of what has happened to the incidence of child labour in our country. It shows that there is a welcome decline in the incidence of child labour from 1993-94 to 2004-05 to 2009-10. While the child workforce participation has come down to two per cent, let us not forget that in the absolute terms, the number of child labour is very large, uncomfortably large. The number that is going around is about 4.35 million children in various kinds of labour. That is why this Bill is a move in the right direction.

Sir, rehabilitation of children and adolescents requires coordination among various Ministries such as Labour, Human Resource Development, Women and Child Development, Home Affairs and Rural Development. But, instead of having a

[Dr. Narendra Jadhav]
fragmented approach with a limited coordination among the Ministries, a new Child Labour Policy ought to have been brought forward, which would specify how the law should be implemented.

The third observation that I want to make is that the Standing Committee has made several recommendations. Some of those very valid recommendations have not been incorporated. For example, this Bill prohibits employment of children in any occupation but some exceptions are given. The Standing Committee had said that this provision about making exceptions available is something that creates loopholes because it is very difficult to keep a check on children working in their homes and finding out whether they are helping their parents or working to supplement their family income. Sir, my suggestion here is that all these exceptions should be removed and the employment should be prohibited in all occupations wherever there is a subordinate relationship of work and labour. This is something which needs to be done.

The next point that I have is that this Bill very rightly prohibits employment of adolescents, that is, between the age-group of 15-18. There, the meaning of hazardous occupations and processes has not been addressed. What the Bill does is to specify that the Central Government may specify the kinds of non-hazardous occupations and processes in which adolescents may be employed.

Sir, I wish to state that the meaning of hazardous occupations and processes should be widened to include all the occupations and processes that may jeopardise health, safety and morale of adolescents in line with the International Labour Organisation Convention-138.

The final point that I would like to make, Sir, is that this Bill empowers the appropriate Government to make periodic inspection of places of employment where employment of children is prohibited and hazardous occupations and processes are carried out. The Standing Committee had noted that while the Bill prohibits employment of children in all occupations and processes, the power to inspect should cover all places of work. In case of adolescents, this power may be limited to those places where hazardous occupations or processes are carried out.

Sir, I commend this Bill but with the modifications which were suggested in my intervention today. Thank you very much, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri A. V. Swamy. He is not here. Shri D. Raja.

SHRI D. RAJA (Tamil Nadu): Thank you, Mr. Deputy Chairman, Sir. I have very strong reservations on this Bill. I have reasons for that. I am one who wanted

this Bill to be referred to a Select Committee for further scrutiny. Even now I hold that view. The Government may consider it. Sir, there are a few key issues. The child welfare must be the centre of our policies whenever we frame policies. They are the future. The intent of the Bill is a good one, but the content has the problem. The implementation has the problem. When I say this, Sir, there is improvement in the situation. I hail from Tamil Nadu. We had one Chief Minister, Mr. Kamaraj. When he was the Chief Minister, he introduced the Mid-day Meal Scheme, but it was a targeted one. The target was the *dalit* children. In those days, the word used was *Harijan*. That was the targeted programme. When Mr. MGR became the Chief Minister, that entire scheme became universal. After Mr. MGR, every successive Government in Tamil Nadu tried to strengthen that Noon Meal Scheme. Now, it has got the national recognition, it has got the global recognition.

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN: Now *Amma* has announced morning meal scheme also.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: She has introduced breakfast also.

SHRIMATI VIJILA SATHYANANTH (Tamil Nadu): Now we have morning meal scheme.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is a good thing.

SHRI D. RAJA: The point that I have been trying to make out is, it helped the State to increase the Enrolment Ratio. Children go to school, but it does not mean other things. Sir, I have a paper showing State-wise details of working children in the age group of 5-14 years as per the Census 2001 and Census 2011. Now, the 2011 Census says that there are 43,53,247 working children between 5-14 age group. This is the Government figure. That includes Tamil Nadu also. Sir, 2011 census says that in Tamil Nadu, there are 1,51,437 working children. I am quoting the official figure. Sir, now I come to the key issues. We will talk about children who are between 6-14 years now. They are children. This Parliament passed the Right to Education Act. They should be in schools. Yes, we want our children to be in schools, but it is not happening. The children are forced to work. They are used for economic and several other exploitations.

The Bill defines 'children' under fourteen years as one category and it says that 'children' between fourteen and eighteen – adolescents – should not work in hazardous occupations. That is what the Bill says.

The Bill also talks about penalties – penalizing parents, guardians, trusts, etc. The Bill speaks about these three key issues. The point here is, the hon. Minister has circulated several amendments to this Bill. In fact, incorporating all these amendments,

[Shri D. Raja]

the hon. Minister should have brought a new Bill and that new Bill should have been referred to a Select Committee. That is my position. Now, the first amendment talks about this. It says, 'Nothing in sub-section 1 shall apply where child helps his family or family enterprise which is other than any hazardous occupations or process set forth in the Schedule after his school hours or during vacations.' Sir, what is family? I am reading the explanation given by the hon. Minister. It says, 'Family, in relation to a child, means mother, father, brother and father's sister and brother and mother's sister and brother.' It can be extended also and you can call it an 'extended family.' Then, what is this 'family enterprise'? Here, the hon. Minister's amendment explains hazardous occupation. It says, 'Provided that the Central Government may, by notification, specify the nature of non-hazardous work to which an adolescent may be permitted to work under this Act.' ...(*Time-bell rings*)... So, these are all consequences. What I am trying to say is 'family enterprise' can be interpreted in many ways and it can perpetuate cost-based occupations also. It can lead to a situation where a manual scavenger's children should continue as manual scavengers or a bidi worker's child should continue as a bidi worker or a handloom worker's child will have to continue as a handloom worker! So, this is a very dangerous clause and this has been questioned by many sociologists in the country. What is this family enterprise? And, you are forcing child to be used in family enterprise! How can you justify this? That is why there are serious key issues involved in this Bill. It should not be passed in haste. And, we are considering a Bill concerning children who are the future of this nation. We should have concern for their welfare.

So, I oppose this Bill. I want the hon. Minister to reconsider his position and try to understand the concerns, refer it to a Select Committee and let us have another scrutiny. Thank you.

श्रीमती रेणुका चौधरी (आंध्र प्रदेश): सर, आज इतने साल की आज़ादी के बाद हम बाल श्रम पर चर्चा कर रहे हैं। यह बड़ी अज़ीब बात है। सर, राजनीति में आए कई माननीय सदस्यों की उम्र गुजर गयी है। And, today, we are discussing child labour! To start with, it is an oxymoron, because child cannot be equated to labour; child is about childhood, innocence, *bhagwan ka roop*. We talk about children in these terms. We equate the term 'child' to this. So, where did this aberration or obscenity called 'labour' get attached to child? When you say 'child labour', in one stroke, you have taken away the childhood. So, you have to, actually, look at it again. I wish the hon. Minister would come to this House and say that this is the right to childhood that we are discussing, because you cannot, possibly, lay down terms and conditions on work which robs children of their childhood.

You rob children of their childhood. But when they become 18 years of age, many of the people who are sitting in Parliament will be going to ask for their Right to Vote. We will go and ask for their Right to Vote after having denied them any right to childhood. Sir, how is it that we continue to make amendments and come back to Parliament? All of us consciously talk about how it affects children, but don't hesitate to just make aberrations possible. Over the years, the Congress has struggled to ensure that a child has a right in making the destiny of this nation. It was the vision of Shri Rajiv Gandhi who said that the country is going to get younger and it is the youth who should have the right to decide their destinies. He empowered them with the right to vote, by giving them this right at the age of 18. Sir, he brought in technology. Today, rightfully, in the world, India is the youngest country. We have the biggest percentage of youth here, which means productivity for the nation. Youth and young people means, we educate them, we export intelligence and we man stations and sub-stations in the world internationally. One in every sixth citizen of the world is an Indian, which means the youth of this country, the children of this country, are not only going to produce and earn for this nation as adults and young adults, but they will also be contributing to global economies, because the world over, population is declining and they do not have people to run their show. Countries like Germany have taken people out of retirement, sought their physical fitness and reemployed them to execute their own policies because they don't have people. Japan has shown the most alarming negative growth in population in recent times, which means every one in sixth citizen is a product of India and this citizen will be working globally, internationally and for India. So, what does India do to invest in human capital? What is it that we do in Parliament and Assemblies? How sad it is that the child vote is not a vote bank! So a few political parties go out to canvass and say कि हम आपके बच्चों के लिए ये सब कुछ देंगे, आप इसीलिए हमें वोट दीजिए। Childhood is not relevant! We barely go asking for mother's vote, making a human vote relevant in this country. But they are not yet vote banks for this great nation of ours. So many years after independence, we still talk and we still bring about child labour amendments to the Bills that exist, and, then, we talk about how great we are. Sir, sadly, India is the biggest home to the child labour. Unfortunately, because of the size of our population, the percentages add up and we are seen as the largest number of child labourers in the world. Till recently, we had the excuse of poverty and social security, that these are some of the reasons. We, actually, look for reasons and say that these are the reasons why we have child labour. We justified it sometimes by saying that, actually, allowing children to work as domestic help gives them food and shelter. This is a conspiracy that is done silently, because this empowers the people to deny a child any rightful working hours. They work in extraneous circumstances. They are not given warm clothes to

[श्रीमती रेणुका चौधरी]

wear during winters. They are not given food in time and they are brutally tortured, as has been exposed by the media repeatedly several times, where they show them being tortured. Frustrations of the people who employ these children are taken out on these poor children. People who employ these children use them as venting boards for their own frustrations and failures in their personal lives.

Then, Sir, we talk of industrial policies, we talk of progress and development, we come and thump our chests in Parliament and we talk about the *achhe din* which are coming, but which have not come so far. But we live in hope. We live in some optimism, praying that some time that dream or mirage will come true; and we see that when we pass industrial policies, we don't implement proper mechanisms. We are so excited about bringing multinationals into our country. But has India ever actually sat down across the table and said, 'Listen, when you come into my country and you want these assets from us, what is your contribution to the children'? Since that is an unchartered territory, you don't hold them accountable and that leads to the use of child labour. The lack of universal education was something that we all witnessed where families themselves said, 'We can't afford to educate our children. So, we will send them out to labour.' It was the Congress that visualized this and we said, 'Yes, that is a reality check. This is where the truth bites us'. We spoke to mothers across the country and they said, 'Yes, as a mother, I too have a dream. I want my child's life to be better than mine. I see television. Shri Rajiv Gandhi gave us the cell phone technology which brought the world into our palms. I am able to see my employer's children sitting in America and I can see their room there and what they are doing. Their photos come in the newspapers. They are big people, great people. I also want that for my child. I don't want my child to be a domestic help'. And, they aren't. There is a change that we saw when we empowered this nation, and, in my own lifetime, I can give you several anecdotes and you can verify them. A stone-breaker and a daily labourer lost his wife, but put his children into a welfare school, the welfare schools which were set up by the Congress Government. These children got educated. The daughter then married a Government School Headmaster and one of her children is an engineer and one tried to get into Med School but it was prohibitively expensive. He got the marks. But he is employed today in another job. This is in my lifetime, and these people are available. You can verify. But these are examples far and few in between. We need to address child labour not in isolation of labour laws but as a cognitive progress which is integrated with all other sections of so-called development and progress. We see people pushing children out of school. Why does that happen? It is not because of the wonderful food that you are giving them at mid-day meal! It

is when you are allotting Special Economic Zones. It is when you give permissions to build dams and you displace people without thinking. We worry about forest and environment. We worry about animal rights. But has anyone addressed what happens to children when they are shifted like that? Do they have access to schools, to Child Care Centres, to immunization policies? Can they afford to be just moved out like baggages or suitcases or pieces of furniture that they will be removed, transplanted from the area where they were born and grow up and suddenly by the stroke of one pen of the Union Government, they are displaced. You can electronically tag trees to count but you don't have identities for your children that they are just moved away. There is no psychological counselor or guidance there. What about my children in conflict areas? Kashmir is burning today. Assam is burning today. Schools are closed. Newspapers are not being printed. We talk about adults and their problems. Have you addressed what happens to children in these situations of that terror, the fear, the insecurity of displacement, seeing their parents horrified and terrified themselves? What do we do to these child minds which are born so pure and fearless? Is this what we do as instruments of change, progress and development that we throw them out? What happens to the children of farmers' suicides?

We talk about it here repeatedly. We discuss agrarian conflict and agrarian failures. Has anyone addressed the question as to what happens to the children of the farmers who kill themselves? What happens when there is an armed conflict? What about the high cost of healthcare? Just this morning we talked about hospitals and the huge exploitation that happens. Sir, what happens to children when a family, as a unit, has to invest in healthcare? The earning member of the family is given the priority. Next, the male child of the family is invested in. The girl child is a dispensable commodity! She can be denied healthcare and she can die! The most poignant, heart-rending news that all of us read recently was that of a couple and their child with a rare kidney disease. They couldn't afford the transplant and so, they actually went to Court and pleaded that they should have the right to kill their child as the child was going to die anyway because it was denied medical aid; they cannot afford it. What happens to such children? That is the tragedy of our times, Sir. We pay so much lip-service here. We address the media and we talk about so many things, but somewhere there is an erosion of values in us as human beings that we allow this to happen. Now, a lot of my hon. colleagues have quoted statistics. But, Sir, there are absolutely no statistics to show us actually what the figures pertaining to bonded labour are. Nobody knows what the figures for bonded labour are.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Renukaji, you are very relevant, but there is one more speaker. So, try to conclude.

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: Sir, I think there is enough time.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: There is one more speaker; that is what I am saying. ...(*Interruptions*)... She took 13 minutes; only 12 minutes remain. Renukaji, try to conclude in five minutes.

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: Sir, it is a form of slavery. Children, who are bonded and in debt because their parents have taken money are then traded.

Sir, I wish to now quote a few examples of what is happening today in our society. Chhattisgarh and Jharkhand are glaring examples of violations of child rights. Meena Khalkho was raped. She was then accused of being a Naxalite and shot and killed by the Forces. The father, to date, says that his daughter was not a Naxalite. So, she becomes a double victim; she is raped and then she is shot dead. And, this system is allowed in 2016, in the era of telecommunication, in the era of transparency and the Right to Information! Nothing protects children and women. That is the tragedy of our times. Did you know about the Jhaliyamri Gaon incident that happened in Kanker district in Chhattisgarh? There is a *Adivasi Balika Ashram* there. Sir, about 40 children were repeatedly raped for a period of two years, many of whom got pregnant and died. What has happened in that case? Nothing, Sir! It did not even make national news. It is not important! They are children! They are the aborted foetuses which we see the dogs drag away and eat. They are abandoned babies whom you recover from Municipal waste bins. And these are for the sexual indulgence of ugly people. But, it is okay! It is accepted! These are the *achche din's* definition that we will keep seeing repeatedly. Aren't we all collectively ashamed and embarrassed a bit that the Supreme Court takes cognizance and passes strictures, and Parliament does not debate this?!

It is the Supreme Court that took cognizance and passed strictures against this vice. Eleven thousand women and children have vanished; they are not on the radar of India. They have disappeared. Houdini could not pull this act off? But the Governments have done it; they have wiped them out from the Census. There is no identity of these people, women and children who have disappeared. ...(*Interruptions*)... प्लीज, आप बैठ जाइए। जरा सब्र से सुनिए। बाद में बोलिएगा। Sir, I am sorry to say this, but these are statistics as Rajaji said. Fire crackers industry, pyrotechnics, diamond industry, in all these places where children are used ...(*Interruptions*)... I have not yielded and this should not go on record, Sir. ...(*Interruptions*)...

श्री राम विचार नेताम (छत्तीसगढ़)ः उपसभापति जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। ...(**व्यवधान**)..

श्रीमती रेणुका चौधरीः आप बैठ जाइए। मैं आपको समय नहीं दे रही हूँ। Sir, I will take

double the time if he goes on talking like this. ...(*Interruptions*)...

श्री राम विचार नेतामः छत्तीसगढ़ के बारे में ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: She is not yielding. ...(*Interruptions*)... She is not yielding. ...(*Interruptions*)...

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: I am not yielding. ...(*Interruptions*)... आप बाद में बोलिए।

श्री राम विचार नेतामः सर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Renukaji, he is on a point of order. ...(*Interruptions*)...

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: I am not yielding. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: On a point of order, you have to. ...(*Interruptions*)... Tell me, what is your point of order?. ...(*Interruptions*)...

श्री राम विचार नेतामः उपसभापति जी, मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर यह है, ...(**व्यवधान**)... उपसभापति जी, एक तो मैं पहली बार यहां आया हूँ और पहली बार बोल रहा हूँ।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What is your point of order? आपको प्वाइंट ऑफ ऑर्डर बोलना है। प्वाइंट ऑफ ऑर्डर बताओ।

श्री राम विचार नेतामः सर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि आप बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) संशोधन विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं, न कि जनरल चर्चा कर रहे हैं। यह मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्रीमती रेणुका चौधरीः आप नए आए हैं, आप समझिए। ...(**व्यवधान**)... बैठ जाइए, सुनिए। फिर आप अपनी टर्न पर बोलिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री राम विचार नेतामः इन्होंने चर्चा के तहत छत्तीसगढ़ के बारे में जिक्र किया। ...(**व्यवधान**)

श्री उपसभापतिः बैठिए, बैठिए। There is no point of order in that. ...(*Interruptions*)...

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: Sir, children are used in bangle industry, fire cracker factories; they are used in dish washing in hotels. They are also used in National Highway *dhabhas*. The Ministry of National Highways should also be involved. What happens to run-away children, whom you find in railway stations, bus stations? People use children as couriers for distributing drugs because the Juvenile Law says that they will get a softer sentence. What happens to terrorists who use children to pass weapons and keep them running in conflict zones? This Bill doesn't spell out anything like that. And now I want to ask, and what Mr. Raja said is right, what do you mean by family. What is 'family enterprise'? Sir, family enterprise can be sexual exploitation. It is the *chacha* or the *mama* from the village who brings

[Shrimati Renuka Chowdhury]
these young girls saying he will get them a job and sells them for sexual trafficking. What is the definition of 'family' in today's society? ...(*Interruptions*)... There are enough researches and enough reports which reflect that the girls who have gone ...(*Interruptions*)... Sir, please, I was the Minister of Women and Child Development and I know how many raids we conducted and how many children sat in terror and told us that they came to the city because they trusted their 'uncle'. This शब्द 'uncle' बड़ी गंदी चीज़ है। यह जो मामा होता है, शायद कंस मामा से शुरूआत हुई, पहचान वहां से हुई है, वहां से लेकर these uncles who come and these aunties who come are quite dangerous. There is no definition of this. How do you propose to identify or certify 'family enterprise'?

Where does this come from? How does it begin? And, I am also shocked and I want a clarification, through you, Sir, on the issue of 'hazardous occupations'. As I have come to learn, the Government has slashed 'hazardous occupations' from 18 activities to 3. How are you redefining 'hazardous occupations'?

SHRI RAVI PRAKASH VERMA: In the name of 'ease of doing business'.

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: Yes. If you want to make human capital out of these children and you believe that you can do it, I am sorry, Sir, I have strong reservations regarding this and unless this porosity in this Bill is plugged, you will not be able to actually address the real issue.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, please conclude.

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: Sir, I am concluding. The list of 'hazardous occupations' has been made over years of process of understanding and eliminating. Now, overnight, you are suddenly authorized that you people come and strike it down and say that only three or four are relevant, बाकी सब बेकार है। This is absurd. You can't do that. We have also learnt that distant relatives are the traffickers, employers and abusers of child labour.

What has happened to the National Commission for Protection of Child Rights? This was something that the Congress Party brought in and we established protection of child rights so that a child, irrespective of the environment, had the accessibility, the affordability and the availability of protection under the NCPCR. That is not even mentioned in this Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: All right. Please conclude now.

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: I am concluding, Sir. What are the monitoring agencies in districts that will actually see this? Would the Government

please consider giving them identity cards? The children below 14 years of age should all be in schools. Regarding your *Anganwadis*, your Mid-Day Meal Scheme, your Child Right Panels, the people, who are supposed to be appointed in the districts, should ensure that the children are in schools. Give the RTE cards to the children in the age group of 6-14 years, so that they can be identified and they cannot be trafficked or sent to labour. Then, you have to see that the children between 14 and 18 years of age are given skill development. ...(*Time bell rings*)... Do not remove the skills that the country has and then talk about skill development. You have got to also discriminate between other skills and the heritage skills which some children learn, whether it is gold making or other skills. Such heritage skills should be nurtured in children after the age of 14 years. This should be taught to them so that they don't lose what they have in their families over centuries; and you instead teach them how to make rexine bags. Thank you very much, Sir, for the patient hearing. Jai Hind.

SHRI RANGASAYEE RAMAKRISHNA (Karnataka): Sir, I rise to support this Bill since it aims to bridge a fundamental gap in our society in the direction of what might be succinctly expressed as '*Bachpan Bachao*'. With the various Amendments moved by the hon. Labour Minister to the 2012 version of this Bill, this Bill is a step in the right direction since it harmonises the seemingly conflicting objectives of the Right to Education Act; the objectives of the Skill India Mission and the dire need to preserve and enrich the *paramparagat* generational continuity in arts and crafts that constitute the idea of India.

I shall commence with the '*Bachapan Bachao*'. When we grow older, the first sign of ageing dawns on us with impaired cognitive faculties and slow but steady progress of impaired memory. But it is a wonderful gift of God that while the memory of our recent past fades, the events in our distant past get etched with clarity in our memory. The glorious years of carefree childhood with all the attendant fun frolic, idiocy and madness comfort us insulating us from the rigours of ageing. As Tom Stoppard says "If you carry your childhood with you, you never become older." But let us introspect on the plight of those millions who never had a *bachpan*, who never had a childhood, mainly because of poverty. While I was studying this Bill, I was filled with wonderment how we have been chasing shadows ceaselessly in our march since 1950 when we gave to ourselves the Constitution of India, particularly the Part IV on Directive Principles of State Policy. Had we brought the Right to Education immediately after 1950, we need not have chased the shadow of adult literacy. By now the entire nation would have become literate. Had we paid heed to Article 39 which cautions the State against the abuse of tender age of children and the need for protecting childhood and youth against exploitation and moral and

[Shri Rangasayee Ramakrishna]

material abandonment, we would have abolished child labour and educated all our society. And, of course, there is Article 44 which talks of Uniform Civil Code, which is still being debated.

Coming to the Bill, this is the first serious attempt to protect childhood. Instead of specific enumeration of occupations or processes in the prohibited list, the present amendment prohibits the employment of children altogether in all occupations and processes, save those categories mentioned in Section 3(2) (a) and (b), both of which ensure that the exemption will be applicable only after school hours and vacations. In this manner, this Bill paves the way for the effective implementation of the Right to Education Act. The present Bill also creates a new category of adolescents, 'Age 14 to 18 years', and prohibits their employment in hazardous occupations and processes specified in the Schedule which can be modified only by the Central Government under its rule-making powers.

While the present Bill is in the direction of giving teeth to the right implementation of the Right to Education Act, I would draw the kind attention of the hon. Minister to a small slip between the cup and the lip. While the aim of the RTE Act is to provide elementary education to all irrespective of age, the current Bill seems to allow adolescents (14 to 18 years) to be employed even if they have not completed elementary education. It seems advisable to make child labour permissible to adolescents only if they have completed elementary education.

There is an apprehension that the exemptions proposed in Section 3(2) (a) and (b) may open the floodgates for continuance of child labour. This is not so. There is an objective behind this section, which is to preserve and continue the *paramparagat* occupations and skills which have been passed on from one generation to another in arts and crafts like handlooms and handicrafts, temple architecture, etc., which really constitute the idea of India. If this safeguard is not there, there is a danger of this legislation deskilling India and then compelling us to search avenues for re-skilling. I would say that only in post-Independence India, we seem to have played havoc with the school curriculum ignoring the need for imparting skills in the primary and middle school level. I recall that during my childhood schooling in a District Board School in Pattukottai in Tamil Nadu during the last days of British Raj, I had to learn carpentry as part of the curriculum.

The aroma of fresh wood shavings in the craft lab of that school is still lingering in my nostrils. I have some reservations on the wholesale exemption to entertainment industry. Working for a few hours outside the school hours for audio

6.00 P.M.

visual advertisements is one thing. But it is altogether a different ball game to engage children in mega serials like Bal Hanuman and Bal Ganesha which run for years and years during which period the child completely forfeits its entire childhood. I would suggest that the Ministries of I and B and Women and Child Development together with the Labour Ministry must constitute a joint committee to work out guidelines for such occupations.

To conclude, the proof of the pudding is in the eating. This Bill entirely depends on the State Governments to make it succeed or fail. Implementation is not necessarily achieved only in prescribing punishments. The focus of this Bill is intrinsically linked with the focus to RTE, the Right to Education. I would hence suggest that the Neighbourhood School is the right place for ensuring that this legislation works. Close monitoring of attendance in these schools should be the preferred route for making this legislation succeed.

The 1986 Act was successful to some extent in curbing child labour in the organised sector. But there is the prevalence of child labour in the pyrotechnic factories of Sivakasi in Tamil Nadu, which is my home State, and the luxury carpet weaving centres in UP and Rajasthan, which used to be my *karmabhoomi*, which employed mainly infant labour. The nimbler the fingers, the higher the knots are broadly the spectra of the past. But the evil has now spread to the unorganised sector. It is my earnest hope that this legislation which we are considering will altogether eliminate child labour and restore childhood to its rightful place. Kofi Annan said, "There is no trust more sacred than the one the world holds with children", and it is this trust in *Bachpan Bachao* which we honour through this historic testament enshrined in this Bill. With these words, I support this Bill. Thank.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you, Shri Ramakrishnaji. Now, Shrimati Vandana Chavan; not present. Now, Dr. K. Keshava Rao.

DR. K. KESHAVA RAO (Andhra Pradesh): Thank you, Sir. First of all, I am very unhappy with the Bill but, at the same time, I support the Bill. Well, life itself is a paradox because of the real situation. The complexities of the socio-economic conditions of this country need to be understood before we talk about child labour. The fact is, it is a curse to be born a poor and crime to live one. We all know this. And that is a reality. This is not a new Bill at all. Just a few amendments have been brought in and I don't think many things are added to it. You have brought in 'adolescent' here. The question today is: Why do we want this child labour to be prevented? You have linked it directly with the RTE. I think all the Members were provoked by the presence of Mr. Javadekar here, the new HRD Minister, and

[Dr. K. Keshava Rao]

started talking about a new education system. This has nothing to do with the new education system. Which no doubt prepares a ground where you don't allow the children to go out and allow them a scope to get into the schools. That is entirely different. But if Javadekar *Saheb* can really attract those boys of that age-group into the schools — not saying schools, but play schools — wherein they can be attracted and taught, things would be different. Then, he has to look into the schooling system; he has to look into the syllabus; he has to look into the monitoring and all these things. That is another matter. I am not trying to talk about the foreign affairs and all other things. I am also not becoming such an emotional like Mr. Ravi Verma. We all know the kind of situation we have inherited. But the question today remains that there are something like half a million child labour. In fact, that is also a wrong figure, if we are taking into account the unorgansied sector, it is more than two crores because 1.3 crores is the agriculture labour in which we are sure 80 per cent people are children. If you take those into account, a lot of people are there. That is the reality situation; that is a reality check.

Now what do we do? We have prohibition of child labour in place. We don't want our children to get out of the school to do work. I am not getting into semantics. Nor do I want to go into its nuances like whether the child work should be called a labour or something else. You can look into these things later. Now how do we face this reality? We have this Bill before us. Earlier also there was a Bill. They thought that that needed some amendments to tighten its clauses. But let me tell you one thing. Dr. Jadhav spoke before me. He raised just five things which I wanted to refer as points.

Sir, the question today is that the Bill that you have brought in has some porosity, as she has observed. I would not consider it as vacuum. First is age. Let me tell the former Advocate-General from Tamil Nadu that the age prescribed in the Bill need not be the age prescribed in other Bills. Age is not a problem here. But, age has become a problem because you have directly linked it with the RTE. What you have said there is, 'either six to fourteen years of age,' I am talking about the RTE, or what the so and so section of the RTE says. That RTE section says, 'until the child completes his elementary education.' The child may complete his elementary education by to fourteenth year or it may take some more years. Having connected that here he has brought in some kind of a distortion or disconnection which the hon. Member from Tamil Nadu was highlighting. They were very pertinent things. You must look into them since you have brought it to notice.

Now the second question that arises is this. You have provided some kind of exemption. You have also brought in 'adolescent sections.' First of all, you totally

banned the child labour. A debate is going on in the world whether it is correct or not. A strong debate is going on in the country about totally banning children from going there. In a particular socio-economic condition, is it right or wrong? Will cause a burden? Or will it solve the problem? I would not go into that. Nonetheless, I think it is a good step provided we are able to implement it. Legislation is neither a permanent solution nor a good solution nor a fool-proof solution of the issues that we raise. It at best gives legitimacy to an issue. We removed dowry but it still continues. Here every Member wanted to know about this. How do we implement it? When we talk about the exemptions that you have brought in like helping family enterprises, we want to know this. What is the monitoring system in place? Since I am involved in labour issues like you, I know that you don't have any inspectorate at all. The implementation is left to the States. What is the strength of the inspectorate there? Have we improved their resources? We have not done that. Now we are trying to monitor the entire families in the country. That will become another problem for you. But it should be there. I am only trying to draw your attention to some of the issues.

You have used the word 'hazardous.' The hon. Member was right in saying that from eighteen you have brought it to three. It is good because you have generalised the subject by mentioning mines and explosives etc. But as far as 'hazardous process' is concerned, you have copied it from the Factories Act. That is not correct here because it is about child labour. That was for the Factories Act. In the Factories Act, we have got 'eighteen' keeping in mind any accident that would lead to certain kind of a situation. When you are talking about a child, what you have done is that in haste, though I don't want to say that, you have copied the same words in the Schedule. That also needs to be looked into. But the saving grace is that you have said that the Central Government, if it wants, can change the Schedule.

Now I come to the issue of exemptions that you have given. You are saying that in these three categories they can work. But there are non-hazardous fields where a man is put to some kind of harassment or moral torture. The ILO Convention C138 spoke about the same thing. It wanted a ban on the child working. They brought up this particular issue about the physical, moral and mental torture that man is put to. We are aiming at the child not going to work at that particular age because he should go to school. He goes to school for eight hours; after that, he goes to work. So, it is an integrated thing. What I am saying is, we have made the best efforts. I think it is an improvement, though it is not enough. Much needs to be done. On the five points which Dr. Jadhav said, I join with him and I agree totally with him. I would again like to remind you that the National Child Labour Project, which you brought in, should come into the picture. If you are trying to

[Dr. K. Keshava Rao]
implement this, don't forget about your NCLP because that could be an answer to many of things you are trying to do. ...(*Time-bell rings*)... You can have your own schooling system with a training program. ...(*Interruptions*)...

Sir, there is another thing, as Members have said. I welcome the object because it is an improvement on the earlier Act and it will continue. But, no policy instrument or legislation like this can be read in isolation, which you have done. There are other enactments. It has to be worked in collaboration and in coordination with other Ministries, particularly HRD, Women and Child Development, etc. A coordinated approach by these three will only be able to achieve this. Thank you very much, Sir.

SHRIMATI KANIMOZHI (Tamil Nadu): Thank you, Sir. I definitely understand the intentions of the Government in bringing forward this Bill. But, we should also think whether the intentions are being actually carried out. The intent might be to prohibit children from working. But, there are amendments which have been brought in this which actually go against the intention of the Bill and we have to understand that. We should also understand that. I am sure in this House everybody has a child at home – a son or a daughter or a grandchild or somebody at home. Would we even dream of thinking that the child should come back home from school and work with us, assist us, go to a shop, sit and assist the father or go to the fields? Will we allow our children at home to do this? None of us would. So, what is not right for our children, what right do we have to expect that from children of other families just because they are not economically empowered? You cannot take away the childhood of children who are not economically empowered. This is exactly what we are trying to do. I think we should really look at that and understand that we are taking away the childhood of the children because they are economically depressed. Child labour is cruel, exploitative, socially and morally dangerous and it should be eradicated entirely. I am sure everybody has the same opinion. I also like to bring to the notice of this House what happened in Tamil Nadu in the early 50s. A system of *Kula Kalvi Thittam* was brought by Rajaji. He said that after school, children should go back home and do what their fathers and families were practising, practise the same occupations, the same kind of work which the parents were practising. It was actually a caste-based education system. You go back home and learn and continue with what your parents, family and caste did. There was a big opposition in Tamil Nadu against this. He was actually made to resign because of this *Kula Kalvi Thittam*, which he brought in the early 50s. After that, Shri Kamaraj, who took over as the Chief Minister, scrapped this. So, I would like to remind you that a Chief Minister was made to resign because the entire State and, especially, the *Dravidian* leaders were against this. They made sure

that the system was scrapped, and I hope that history will not repeat itself in the Central Government. I would like to bring this to the notice of this House.

We are talking about dropout rates in schools. Of course, my friends were taking credit for something which happened in 2010 in Tamil Nadu. The dropout rate was brought to 99.3 per cent. ...(*Interruptions*)... Yes. I am just saying it was in 2010. ...(*Interruptions*)... Yes, 2010. ...(*Interruptions*)...

SHRIMATI VIJILA SATHYANANTH: No, no.....(*Interruptions*)...

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN: Sir, in the year.....(*Interruptions*)... The UNESCO report is there. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. ...(*Interruptions*)... Let her speak. ...(*Interruptions*)... No, no. ...(*Interruptions*)... An hon. Lady Member is speaking, and another lady Member should not obstruct. ...(*Interruptions*)... A lady Member should not obstruct. ...(*Interruptions*)... Shri Navaneethakrishnan. ...(*Interruptions*)... Navaneethakrishnanji, please. ...(*Interruptions*)... Let her speak.....(*Interruptions*)...

SHRIMATI KANIMOZHI: Sir, I am not talking about child labour at all. ...(*Interruptions*)... Sir, if Tamil Nadu does not have child labour, I am the happiest. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Let her speak. ...(*Interruptions*)... You continue. ...(*Interruptions*)... You continue. ...(*Interruptions*)... You address the Chair. ...(*Interruptions*)...

SHRIMATI KANIMOZHI: I am very proud that Tamil Nadu does not have child labour. I am very proud. ...(*Interruptions*)... I am very happy. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You address the Chair. ...(*Interruptions*)... Don't look there. ...(*Interruptions*)... Address the Chair and continue your speech. ...(*Interruptions*)...

SHRIMATI KANIMOZHI: Sir, we know of the dropout rates in schools. It is just not because the children cannot go to school. Now, the emphasis is on private schools. In many States, even in Tamil Nadu, many of the parents think that private schools are much better than Government schools. The Minister is here and I take this opportunity to bring it up and to make sure that the public education system is improved. I am not talking about the Central Government-run schools only. I think, the Central Government should assist them to make sure that these schools are up to the mark. There are instances of the Government closing down the State Government schools. This should be stopped to make sure that education is made affordable to everybody and not that everybody has to send their children to private schools to get the best education.

[Shrimati Kanimozhi]

One more issue is there. Do we really care about educating our children or are we trying to bring out concrete blocks similar to each other from our education system? I was talking to a child once as to why he hates school system so much. He told me about the education system and how exams here are like. This education system here is like asking a bird, a fish, a dog and a snake to climb a tree and then say that the one, who can climb the tree the best, is the best. That one gets the highest marks. What does a bird, fish or dog gain by climbing a tree? Nothing! But then most of our education system is aimed at doing that. They do not care about the children who have difficulties in learning. So, these children drop out. We do not care about helping them. We do not care about reaching out to them. These children turn towards working because they have no choice for their future. So, they immediately take up a job because the society and family condemns them as useless. I think, education has to be inclusive to stop child labour.

Apart from that, we also have to understand one important thing. This Bill says that children can go back home and help parents. How many parents are really aware of what is hazardous to the children and what is not? Not many parents are that aware or equipped enough to understand what can be hazardous to a child. There are so many such parents. We know that parents do not willingly or knowingly send their children to work in fireworks factory or cotton yarn factory. They do not know what will happen to their children, how their children's health will be affected.

But they still send them because they are not aware. We know what happened in Kerala because of Endosulfan; how many unborn children were affected. So how many parents are really aware as to how pesticides will affect the children? Would we allow our children, in our homes, to do that? We will not. Today, the school curriculum is so difficult for every child. If you expect a child to come back from school and help you in the kind of occupation you have been carrying out, how will the child finish the homework which is so much? How do they prepare for the tests? Practically, every school believes in having a test every second day. How do they prepare? So you are actually encouraging children to drop out from schools and take up jobs.

Child labour is one of the most important things. We cannot, actually, segregate child trafficking and child labour; they are inter-connected. Children, who are trafficked, are mostly employed as cheap labourers in construction sites, domestic works, factories and sold for child prostitution. During the period between 2010-2014, there were 3.85 lakh missing children, which means more than 77,000 children go missing every year and among them, 63 per cent are girls. More than 40 per

cent of them remain untraced even till today, over the years. So this Act should recognise these facts and should provide for rehabilitation of children and adolescents rescued. I think the Standing Committee has also insisted that rehabilitation is very important and it cannot be taken up by just one department, not just by the Labour Department, but, by all the Departments, Women and Child Welfare Department, HRD, Rural Development Department. There should be a concentrated effort by all the departments coming together to rehabilitate these children. Without that, nothing can really be changed in their lives. On the one hand, the Government is pushing for schemes such as Skill India and Skill Certification, and the same Government is indifferent to the plight of child labourers. We cannot say that a child is a child only till 14. Science has accepted and, all over the world, it is accepted that a child is developing emotionally till the age of 18. So we cannot take the childhood away. We cannot make the child to go and work just because they have crossed the age of 14. And working atmosphere is not easy for any child. No employment is going to be considerate. We have seen how they have been exploited. We have seen the abuses, and, especially, when it is a girl child, we have also seen cases of sexual abuses happening. I think our children have to be protected. Again, I would like to raise this point that what we will not want for our children, I think, we cannot allow any child in this country to undergo. Thank you, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is the standard to be measured – what we don't want our children to do, should others do? It is a good thing. Now, Shri Madhusudan Mistry.

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN: Sir, one minute. Sir, fourteen poor children have been provided with financial assistance to study Medicine and Engineering by the hon. Chief Minister, Amma, this year. Sir, it must be on record.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. All right; it is already on record. Sit down. ...(*Interruptions*)... Once you have said, and it is on record.

SHRI DEREK O'BRIEN (West Bengal): Sir, we want a Short Duration Discussion on this.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Do you also want something on record? Mr. Derek O'Brien, you don't want something on record!

SHRI MADHUSUDAN MISTRY (Gujarat): Sir, thank you very much for allowing me to speak. Sir, I have two-three questions for the Minister. I just want to ask him as to who represented to him to bring this law. Why are you changing the definition or amending the definition? Has anybody, any parent, any parents' association came to you to say, make it from 'child labour' to 'adolescents' or is it

[Shri Madhusudan Mistry]

suo motu from the Government side? Whom are you making the way for? Is it for industries, multinationals or the promises you made during the elections? Why? If I have an income and if I have enough money, I will not send my children to work at the age of 15-18. I will better send them to schools and colleges. So, whose children you want to employ? Is it lower middle class or upper middle class or top class children? It is a very serious question. I want the Minister to reply to it. At whose behest are you bringing this Bill?

Number two is under your domain. While I was studying in 8th or 9th class, I worked at the age of 15 for ₹ 1 in Ahmedabad Cantonment Board. My children are not working because I have enough income. My grand children never heard of child labour. The point I am making is: Why don't you increase the minimum wages of the working class so that they have enough income to send their children to schools rather than amending this law?

I am quite surprised at the attitude of the Government as such. Whose children do they want to send as labour? It seems the entire working class is at your disposal and you want to send them anywhere you like.

Look at the agriculture sector. The minimum wages in this sector have not been increased for years. You have recommendations of the Seventh Pay Commission. But what about the minimum wages for the sectors under your Department? Why are your officers not thinking about it? That is my question to you.

Number three, what machinery does the Labour Department have? One Labour Officer is a Labour Officer under the Payment of Wages Act. He is under the Factories Act. He is under the Inter-State Migration Workers Act. He is also under the Child Labour Inspector. Under so many laws he is the Inspector. How many inspections he does in one year? What measures do you have to see the States are implementing these laws or not? What control do you have over the State Labour Departments? Did you look at the laws which are being enforced by the States?

My State, Gujarat is a model State. That is what they say despite the fact that the *Dalits* were beaten up badly in the State; and that is agitating the country. But the fact is that out of 4.2 million child labour which has been enumerated by the Census of India, the highest number is in Gujarat. What kind of a model do we have?

Recently, I went to Jamnagar from Ahmedabad which is 400 to 500 Kms. All the big industries have been employing them. What remedy do you have? What control do you have over the State Labour Department? What are you giving them? Have you ever taken a stock of how your Department is functioning as far as the

enforcement at the lower level is concerned? I was defeated simply because of raising the issue of child labour in agriculture in my Constituency; and farmers didn't like it. All the children were employed by an agency of Rajasthan which has brought cotton seeds in order to process them. We are the highest cotton producing State in the country. There is no machinery; there is no law for prosecution. In front of our eyes, wherever you officers go on the national highways, they can find children working in *dhabas*. What action have they taken? Have they ever asked the State Labour Department as to how they are functioning? These are the issues to which you must reply in this House. How are you going to strengthen this? Regarding the functioning of the Department, and the resources that they have, it is a very serious question. Labour Department is the biggest casualty on the advent of liberalization. They have no control over it.

The Prime Minister is from my State. I know how things are working in the entire industry, whether it is agriculture, whether it is the carpet industry, or, whether it is the sea-coast sector. It is everywhere. There are no laws. They do not exist. While replying to the debate, will he answer these questions? Otherwise, I do not think we should support the Amendment Bill. I feel that the Government must reply to all these very basic questions before bringing this law at the ground level.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, the hon. Minister.

SHRI BANDARU DATTATREYA: Mr. Deputy Chairman, Sir, I am really very happy. I feel that it is a historic day because this Bill, the Child Labour (Prohibition and Regulation) Amendment Bill, 2012… ...(*Interruptions*)...

SOME HON. MEMBERS: Sir, we are not able to hear him. ...(*Interruptions*)...

SHRI BANDARU DATTATREYA: Sir, I am happy that it is a historic Bill that I have brought before this august House. And I am also happy at the fact that fifteen hon. Members have participated in the discussion. The intentions of all the hon. Members are very clear, and they are very serious about the eradication of child labour, irrespective of their Party and other affiliations. I am happy for that.

First of all, Sir, I thank the hon. Prime Minister who has entrusted me with this responsibility of the Labour and Employment Ministry. I will reply to the observations made by the hon. Members a little later. But let me tell you, Sir, this amendment is very special and personal for me. I will narrate one incident to you. Of course, I will not take much of your time. I will shortly narrate how child labour exists, how family professions exist, how family enterprises exist. The thing is that it is a landmark amendment. First of all, employment of children below the age of 14 years is banned. No child below the age of 14 years can be employed in any

[Shri Bandaru Dattatreya]
establishment, in any occupation and so on. This is the first thing. Secondly, it is linked to the Right to Education Act of 2009. I need not elaborate it because most of the hon. Members have said something about the age, which age for elementary education, which age for higher education and so on. I will not go into that debate. But, regarding the second point, which I wanted to impress upon all of you, is – the first was about the total ban on employment of children below the age of 14 years... ...(*Interruptions*)... Please. ...(*Interruptions*)... Please. ...(*Interruptions*)...

SHRI HUSAIN DALWAI: Where is the total ban? They can work in family enterprises. ...(*Interruptions*)…

SHRI BANDARU DATTATREYA: Let me clarify this. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: First, you let him complete.

SHRI BANDARU DATTATREYA: First, we have brought in a new category of persons called 'adolescent' about which the provision says that a child between the age of 14 and 18 years cannot be employed in hazardous occupations. …(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, please. Don't do running commentary.

SHRI BANDARU DATTATREYA: Yes, please try to understand it. I will reply to all your points. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I told you not to do any running commentary, please.

SHRI BANDARU DATTATREYA: I will reply to all the issues raised by you shortly. Shortly I will answer it because in hazardous areas and other areas, we have totally banned it.

Thirdly, regarding the punishment, we have made it very stringent. About that also I will tell you shortly. But the main objective of this Bill is, total eradication of child labour, and we have made the violation of the provisions of this Act a cognizable offence, that is, cognizable offence for an employer, not for guardians, not for parents. With regard to its violation by parents, there is only penalty. That is why we have studied it from a wholesome perspective. We have not gone ahead with it in a piecemeal manner. We have taken into consideration all its aspects.

Further, I am submitting before this august House that the Department-related Standing Committee on Labour and Employment has deliberated on this Bill thoroughly and they have given ten recommendations. Out of ten recommendations, I have accepted six recommendations *in toto*; the seventh one has been accepted partially by me. As for the issues which the hon. Members have raised, one was,

below the age of 14 years, employment of children should be totally banned. We have given exception to family and enterprise. Please try to understand it. Why am I telling this? Any Government or any responsible Government, if they want to formulate a policy, they have to go into the details of the entire issue. That is number one. Secondly, it should be implemented in the context of ground reality. Thirdly, in India, a large number of occupations are there. I come from a very poor family. The entire community is depending on these occupations. Like that, farmers are there. One of the hon. Members has stated that artisans are there. Crores and crores of people are depending on artisanry. They are run by their own family members. ...(*Interruptions*)... Shrimati Renuka Chowdhury, I will explain it to you. You are from Telangana. I will convince you. I have a very clear definition of a family. ...(*Interruptions*)... Vermaji, I will explain it to you. I have heard you well. ...(*Interruptions*)... Half knowledge is dangerous. ...(*Interruptions*)...

श्री नीरज शेखर (उत्तर प्रदेश): यह आपको सोचना चाहिए। ...(**व्यवधान**)... इसकी नॉलेज आपको है। ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Let the Minister complete the answer ...(*Interruptions*)... Please sit down. ...(*Interruptions*)... Mr. Minister, you continue to speak.

SHRI BANDARU DATTATREYA: In the definition of a family, safeguards are also kept. The definition of a family is, child's mother, father, brother and sister, and others. Others mean father's brother and sister and mother's brother and sister ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Let him explain ...(*Interruptions*)... I am not allowing this. Let the Minister complete his reply ...(*Interruptions*)...

SHRI NEERAJ SHEKHAR: We have half knowledge ...(*Interruptions*)...

SHRI BANDARU DATTATREYA: In this definition, only the family.. भारत देश में गरीब लोग हैं। जो बच्चा, किसी भी परिस्थिति में माता या पिता को खो देता है, उसको अपने रिलेटिव के पास जाकर रहना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। उसे काम सीखना पड़ता है, उसकी देखभाल करनी पड़ती है। यह स्थिति मेरे साथ भी आई है। ऐसे ही अभी भी काफी लोग family enterprises में सहायता करते हैं, लेकिन बाकी किसी भी family process में किसी को भी allowed नहीं है। इसलिए मैं stricter punishment लाया हूँ। यह मामूली punishment नहीं है, बहुत बड़ी punishment है। इसमें मैंने सुझाव भी दिया है। Guidelines में यह कहा गया है कि बच्चा केवल family की help कर सकता है, वह भी school hours के बाद। मैं आपको अपना example बताना चाहता हूँ। मेरे पिता बचपन में गुजर गए। मेरी माताजी उस्मानगंज जाती थीं, वे उस्मानगंज में प्याज बेचती थीं। अपनी माताजी की सहायता करने के लिए स्कूल के बाद मैं उनके साथ जाता था। मैं उनके साथ इसलिए जाता था, क्योंकि मेरी माताजी मुझसे बोलती थीं, "बेटा, मेरे लिए एक आदमी को रख कर उसको वेतन देना बहुत मुश्किल है। आप लोगों को पढ़ाना

[Shri Bandaru Dattatreya]

और पालना ही मेरे लिए बहुत मुश्किल है। एक और आदमी को लगा कर उससे काम करवाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है।" इसलिए मैं अपनी माताजी के साथ 5 बजे से 7 बजे तक रहता था। जो vacations होते थे, उनमें मैं ही वहां जाता था। मेरी माताजी खाना पकाती थीं और मैं वहां जाकर auction में प्याज खरीदता था। मैंने सीखा। इंडिया में बहुत से ऐसे लोग हैं, जिन्हें माता के, पिता के vocation से सीखना है। India is a different country. भारत एक बहुत अनोखा देश है। इस भारत की संस्कृति को, अपनी social conditions को हमें समझना पड़ेगा। अगर labour laws को लेकर इसको child labour बनाया जाता, तो मैं जेल जाता और मेरी माताजी भी जेल जातीं। इसलिए मैं आपसे request करना चाहता हूँ कि family enterprises में हम लोगों ने beyond school hours को रखा है।

दूसरा, it is a very important thing. There is no employee and employer relationship. There is not at all any employee and employer relationship. इसमें employee and employer relation नहीं है। Family enterprises में कोई वेतन नहीं दिया जाता है। कोई मेडिकल की शॉप चलाता है, उसमें आदमी बाहर जाता है, तो बच्चा घर में रहता है। किराने की दुकान में उसे माता-पिता की help करनी पड़ती है। अगर मैं इसको गुनाह कहूँ, तो इससे कितना exploitation हो जाएगा! इसको लेकर कितने लोग complaint करके कितने केसेज डालेंगे! इसीलिए यह practical रूप में है। Practical रूप में यह सुझाव लाया गया है। इतना ही नहीं, आप मेरे पास अलग से बैठिए, मैं आपको इसके बारे में और समझाऊँगा। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूँगा। Family enterprises और इसके बाद hazardous process के बारे में भी आप लोगों ने कहा। मैंने hazardous occupations or process के बारे में जो लिस्ट दी है, रेणुका जी ने लिस्ट के बारे में बताया, मैं उस लिस्ट का भी खुलासा करूँगा, लेकिन hazardous occupations or processes के बारे में भी adolescent की age हम लोगों ने 15 - 18 साल रखी है। 15 - 18 years, जब वह adolescent हो गया, तो hazardous occupations or processes में it is totally banned. Now, there will not be any which were there in the earlier list. There will be only three things - Inflammable substances or explosives, mines and hazardous process. Only these three things are there.

Number two, it is universal. When it is going to be universal, why do you see the old list and the new list? There will not be any of these at all. If at all any new list is there, we will prepare. Like, even today, there are small shops. छोटी-छोटी दुकानों में काम करने वाले बच्चे हैं, कई बच्चे मॉल्स में भी काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसे बच्चे लिस्ट में नहीं हैं। हम एक नई लिस्ट बनाएंगे और नयी लिस्ट के साथ ऐसे लोगों पर कार्यवाही की जाएगी। ...(**व्यवधान**)... ऐसा नहीं है कि ऐसे बच्चों को लिस्ट से निकाल दिया गया है, हमने उन्हें निकाला नहीं है। We have made it universal. Please go through the Bill in detail. आप लोग डिटेल में जाइए। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, please go through 'family enterprises, hazardous and stricter punishment.' Stricter punishment में मैं एक ही बात आपके सामने बताना चाहता हूं, इसमें जो existing penalty है, इसे आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। अभी हमारे सुब्बारामी जी यहां नहीं हैं, उन्होंने इसमें अमेंडमेंट दिया है। इसमें मैंने जो दिया है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। जो existing penalty है, वह

मिनिमम 10,000 रुपए है। In the existing penalty, in the first offence, the minimum penalty is ₹ 10,000. It may be extended to ₹ 20,000 with a fine. Now, I have enhanced it. The minimum would be ₹ 20,000 which may be extended to a maximum of ₹ 50,000. It is a fair amount. Thirdly, in addition to fine, there is imprisonment provision also. The minimum term earlier was three months and the maximum was one year. Now, I have enhanced the minimum term from six months to two years. It is for the first offence. When a second offence comes, I have increased the period of imprisonment. Earlier it was ranging from six months to two years. Now, I have increased it and it is ranging from one year to three years. So, this is a big signal. It is a big warning for any employer who violates the provisions. He will be punished strictly under the law. So, we are making a stricter punishment.

The fourth is an important aspect. I want to inform this august House that we have made a provision for creation of a Child Adolescent Labour Rehabilitation Fund. We have made a separate provision. In this rehabilitation scheme, I am happy to say that the Odisha Government, Tamil Nadu Government and some other State Governments are having best practices. We are happy about it.

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN: In Tamil Nadu, there is no child labour. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Why is Mr. Navaneethakrishnan getting up for everything? ...(*Interruptions*)...

SHRI BANDARU DATTATREYA: Sir, I have made a provision for participation of the State Governments. If a child is liberated in a State, the State Government has to make a contribution of ₹ 15,000, on its own for freedom. ₹ 15,000 should be provided by the respective State Governments. We would like to involve more State Governments and see to it that violators are punished strictly.

I would like to speak on another two-three aspects. Madhusudan Mistryji was saying something. You may have your own perceptions. My perception is only development agenda. My perception is not to get into debate with anybody. You are mentioning minimum wages and other things. I will talk on it on a different platform. But, regarding the child labour, please understand that it is not the pressure of the Governments, it is the pressure of the NGOs. There are some of the highly respected NGOs like Bachpan Bachao Andolan. मुझे हजारों-हजार एनजीओज़ के लोग मिले, उनसे चर्चा हुई, बातचीत हुई, उनके साथ मैं बैठा। उनके साथ बैठने के बाद जो प्रैक्टिकल बातों पर चर्चा हुई, उसके बाद मैं ये अमेंडमेंट्स लाया हूं। हमारे राजा जी अभी यहां नहीं बैठे हैं, वे चले गए हैं। I respect the CPI leader, Mr. Raja. राजा जी बोल रहे थे कि इस बिल को कमेटी में ले जाना चाहिए।

[Shri Bandaru Dattatreya]

सेलेक्ट कमेटी बनाओ। चार-पांच सालों से यह बिल पेंडिंग है, फिर सेलेक्ट कमेटी को जाना, इस तरह यह बच्चों के साथ अन्याय होगा, 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम करवाना अन्याय होगा। अगर यह कानून आ जाए, तो जैसा आपने बोला, बच्चों के बचपन के जीवन में आनंद होना चाहिए, संतोष होना चाहिए, उन्हें खेलना चाहिए, वह होगा, लेकिन आज वह परिस्थिति नहीं है। हम कानून बनाएंगे और कानून बनाने से इस देश में 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे से कोई भी एम्पलॉयर काम नहीं करवा सकेगा। इसलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है।

लास्ट्ली, हमारी स्कीम जो है, नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट, एनसीएलपी। इस एनसीएलपी स्कीम को भी मैंने देखा है। तमिलनाडु की मैडम पर्सनली आई थीं, उन्होंने भी कहा था। हम एनसीएलपी स्कीम को आगे बढ़ा रहे हैं और इसको आगे बढ़ाकर हमने इस स्कीम में ज्यादा पैसा खर्च किया है। इसमें bridge education is very important. जैसा आप लोगों ने सुझाव दिया स्किल डेवलपमेंट करना चाहिए, तो उनके लिए हम स्किल एजुकेशन का भी प्रावधान करेंगे और प्रावधान करके स्किल एजुकेशन के बाद उनको एम्प्लॉयमेंट दिलाने का काम भी हम कर रहे हैं। यह स्किल डेवलपमेंट स्कीम भी एक बड़ी स्कीम है। एक और इंपॉर्टेंट विषय आईएलओ का है, जिसके बारे में कुछ लोगों ने कहा। आईएलओ का अपना स्टैंडर्ड है। This Bill is aligned with the statutes of the ILO Commission. I am humbly submitting to the House about these two Conventions, *i.e.* 138th and 182th. The 138th Convention, 167 countries have adopted and the 182nd Convention, 171 countries have ratified. Now, if we pass this Bill we will also be in line with the ILO. That is why I humbly appeal to all hon. Members to support this Bill wholeheartedly. Shri Ramakrishna made another suggestion. That suggestion is there. We will examine child labour along with other Ministries, the HRD Ministry, the Women and Child Development Ministry. We will once again sit and see that some of the guidelines are formed, and we are going to have a national policy on child labour. So, that is why I once again appeal to all the hon. Members to pass this Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, the question is:

> "That the Bill further to amend the Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986, be taken into consideration".

The motion was adopted

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 4 were added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall, now, take up Clause 5. There are three Amendments, *i.e.* Amendment (No. 12) by Shri Husain Dalwai, Amendment (No. 21) by Dr. T. Subbarami Reddy and Amendment (No. 3) by Shri Bandaru Dattatreya. Now, Shri Husain Dalwai, are you moving?

CLAUSE 5 - SUBSTITUTION OF NEW SECTION FOR SECTION 3

Prohibition of Employment of children in any occupation and process

SHRI HUSAIN DALWAI: Yes. Sir, I beg to move:

(12.) That in the List of Amendments dated the 15th July, 2016, *for* amendment No. 3, the following be *substituted*, namely:-

"3. (1) No child shall be employed or permitted to work in any occupation or process.

(2) Nothing in sub-section (1) shall apply where the child works as an artist in an audio-visual entertainment industry, including advertisement, films, television serials or such other entertainment or sports activities except the circus, subject to such conditions and safety measures, as may be prescribed:

Provided that no such work under this clause shall affect the school education of the child.

Explanation.— For the purposes of this section, the expression "artist" means a child who performs or practices any work as a hobby or profession directly involving him as an actor, singer, sports person or in such other activity as may be prescribed relating to the entertainment or sports activities falling under sub-section (2).".

The question was put and the motion was negatived.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Dr. Subbarami Reddy. He is not present. So, amendment is not moved. Now, Shri Bandaru Dattatreya to move the amendment.

SHRI BANDARU DATTATREYA: Sir, I move:

(3) That at page 2, *for* lines 15 to 20, the following be *substituted,* namely :-

"3. (1) No child shall be employed or permitted to work in any occupation or process.

(2) Nothing in sub-section (1) shall apply where the child,-

(a) helps his family or family enterprise, which is other than any hazardous occupations or processes set forth in the Schedule, after his school hours or during vacations;

(b) works as an artist in an audio-visual entertainment industry, including advertisement, films, television serials or any such other entertainment or sports activities except the circus, subject to such conditions and safety measures, as may be prescribed:

[Shri Bandaru Dattatreya]

Provided that no such work under this clause shall affect the school education of the child.

Explanation– For the purpose of this section, the expression,

(a) "family" in relation to a child, means his mother, father, brother, sister and father's sister and brother and mother's sister and brother;

(b) "family enterprise" means any work, profession, manufacture or business which is performed by the members of the family with the engagement of other persons;

(c) "artist" means a child who performs or practices any work as a hobby or profession directly involving him as an actor, singer, sports person or in such other activity as may be prescribed relating to the entertainment or sports activities falling under clause (b) of sub-section (2).".

The question was put and the motion was adopted.

Clause 5, as amended, was added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall, now, take up Clause 6. There are two amendments. Amendment (No. 22) by Dr. T. Subbarami Reddy. He is absent. Amendment (No. 4) by Shri Bandaru Dattatreya. Are you moving?

CLAUSE 6 – INSERTION OF NEW SECTION 3A

Prohibition of employment of adolescents in certain hazardous occupations and processes

SHRI BANDARU DATTATREYA: Sir, I beg to move:

(4) That at page 2, *after* line 23, the following be *inserted*, namely:-

"Provided that the Central Government may, by notification, specify the nature of the non-hazardous work to which an adolescent may be permitted to work under this Act.".

The question was put and the motion was adopted.

Clause 6, as amended, was added to the Bill.

CLAUSE 7 – AMENDMENT OF SECTION 4

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up Clause 7. There is one amendment (No. 13) by Shri Husain Dalwai. Are you moving?

SHRI HUSAIN DALWAI: Yes, Sir, I am moving. I beg to move:

(13) That at page 2, clause 7, be *deleted*.

The question was put and the motion was negatived.

Clause 7 was added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: There is insertion of a new Clause 7A by the Minister.

NEW CLAUSE 7A — AMENDMENT OF SECTION 5

SHRI BANDARU DATTATREYA: Sir, I beg to move:

(5) That at page 2, *after* line 26, the following be *inserted*, namely:-

"7A. In section 5 of the principal Act,-

(i) In the marginal heading, for the words "Child Labour Technical Advisory Committee", the words "Technical Advisory Committee" shall be substituted.

(ii) In sub-section (1), for the words "Child Labour Technical Advisory Committee", the words "Technical Advisory Committee" shall be substituted".

The question was put and the motion was adopted.

Clause 7A was added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall, now, take up clause 8 of the Bill. There is one amendment (No. 6) by the Minister. Are you moving?

CLAUSE 8 – OMISSION OF PART III

SHRI BANDARU DATTATREYA: Sir, I beg to move:

(6) That at page 2, *for* line 27, the following be *substituted*, namely:-

"8. In the heading of Part III of the principal Act, for "CHILDREN" substitute "ADOLESCENTS"

The question was put and the motion was adopted.

Clause 8, as amended, was added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, there is also an amendment (No. 7) to clause 8 by the Minister for insertion of new Clauses 8A to 8H. Mr. Minister.

NEW CLAUSES 8A TO 8H

SHRI BANDARU DATTATREYA: Sir, I beg to move:

(7) That at page 2, *after* line 27, the following be *inserted*, namely:-

"8A. In section 6 of the principal Act, *for* the word and figure "section 3", the word, figure and letter "section 3A" shall be *substituted*".

"8B. In section 7 of the principal Act, *for* the word "child", wherever it occurs, the word "adolescent" shall be *substituted*".

"8C. In section 8 of the principal Act, *for* the word "child", the word "adolescent" shall be *substituted*."

"8D. In section 9 of the principal Act, *for* the word "child", at both the paces, where it occurs, the word "adolescent" shall be *substituted*".

"8E. In section 10 of the principal Act, *for* the word "child", at both the places, where it occurs, the word "adolescent" shall be *substituted*".

"8F. In section 11 of the principal Act,

(a) *For* the word "children", the word "adolescents" shall be *substituted*.

(b) *For* the word "child", wherever it occurs, the word "adolescent" shall be *substituted*".

"8G. In section 12 of the principal Act, -

(a) in the marginal heading, *for* the words and figures "section 3 and 14", the words, figures and letter "sections 3A and 14" shall be *substituted*.

(b) *for* the words and figures "sections 3 and 14", the words, figures and letter "section 3A and 14" shall be *substituted*.

"8H. In section 13 of the principal Act, for the word "children", wherever it occurs, the word "adolescents" shall be substituted".

The question was put and the motion was adopted.

Clauses 8A to 8H were added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up clause 9. There are two amendments (Nos. 14 and 15) by Shri Husain Dalwai. Are you moving the amendments?

SHRI HUSAIN DALWAI: No, Sir. I am not moving.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: There are three amendments (Nos. 23, 24 and 25) by Dr. T. Subbarami Reddy. He is not present. And, there are two amendments (Nos. 8 and 9) by the Minister. Mr. Minister.

CLAUSE 9 – AMENDMENT OF SECTION 14

SHRI BANDARU DATTATREYA: Sir, I beg to move:

(8) That at page 3, *after* line 3, the following be *inserted*, namely:-

"(1B) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) and (1A), the parents or guardians of any child or adolescent referred to in section 3 or section 3A, shall not be liable for punishment, in case of the first offence.";

(9) That at page 3, *for* lines 4 to 8, the following be *substituted*, namely:-

"(b) for sub-section (2), the following sub-sections shall be *substituted*, namely:-

(2) Whoever, having been convicted of an offence under section 3 or section 3A commits a like offence afterwards, he shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than one year but which may extend to three years.

(2A) Notwithstanding anything contained in sub-section (2), the parents or guardian having been convicted of an offence under section 3 or 3A, commits a like offence afterwards, he shall be punishable with a fine which may extend to ten thousand rupees.".

The questions were put and the motions were adopted.

Clause 9, as amended, was added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up clause 10 of the Bill. There are three amendments (Nos. 16 and 17) by Shri Husain Dalwai and (No.10) by Shri Bandaru Dattatreya.

CLAUSE 10 – INSERTION OF NEW SECTION 14 A

Offences to be cognizable

SHRI HUSAIN DALWAI: Sir, I move:

(16) That in the List of Amendments dated the 15th July, 2016, amendment No. 10, *for* new section 14C, the following is *substituted*, namely:-

"14C. The child or adolescent, who is employed in contravention of the provisions of this Act and rescued, shall be rehabilitated in accordance with the rules as framed by the Central Government in this regard under this Act".

[Shri Husain Dalwai]

(17) That in the List of Amendments dated the 15th July, 2016, amendment No. 10, in section 14D, *after* sub-section (3), the following proviso be *inserted*, namely:-

"Provided that a record of such composition shall be maintained by the District Magistrate along with details of the accused person according to the rules framed under this Act."

The questions were put and the motions were negatived.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Bandaru Dattatreya, are you moving?

SHRI BANDARU DATTATREYA: Sir, I beg to move:

(10) That at page 3, *for* lines 10 to 13, the following be *substituted*, namely:-

"10. After section 14 of the principal Act, the following sections shall be inserted, namely:-".

2 of 1974 "14A. Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973, any offence committed by an employer and punishable under section 3 or section 3A shall be cognizable.

"14B. (1) The appropriate Government shall constitute a Fund in every district or for two or more districts to be called the Child and Adolescent Labour Rehabilitation Fund to which the amount of the fine realized from the employer of the child and adolescent, within the jurisdiction of such district or districts, shall be credited.

(2) The appropriate Government shall credit an amount of fifteen thousand rupees to the Fund for each child or adolescent for whom the fine amount has been credited under sub-section (1).

(3) The amount credited to the Fund under sub-sections (1) and (2) shall be deposited in such banks or invested in such manner, as the appropriate Government may decide.

(4) The amount deposited or invested, as the case may be under sub-section (3), and the interest accrued on it, shall be paid to the child or adolescent in whose favour such amount is credited, in such manner as may be prescribed.

Explanation. – For the purposes of appropriate Government the Central Government shall include the Administrator or the Lieutenant Governor of a Union Territory under article 239A of the Constitution.

14C. The child or adolescent, who is employed in contravention of the provisions of this Act and rescued, shall be rehabilitated in accordance with the laws for the time being in force.".

14D. (1) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal
2 of 1974. Procedure, 1973, the District Magistrate may, on the application of the accused person, compound any offence committed for the first time by him, under sub-section (3) of section 14 or any offence committed by an accused person being parent or a guardian, in such manner and on payment of such amount to the appropriate Government, as may be prescribed.

(2) If the accused fails to pay such amount for composition of the offence, then, the proceedings shall be continued against such person in accordance with the provisions of this Act.

(3) Where any offence is compounded before the institution of any prosecution, no prosecution shall be instituted in relation to such offence, against the offender in relation to whom the offence is so compounded.

(4) Where the composition of any offence is made after the institution of any prosecution, such composition shall be brought in writing, to the notice of the Court in which the prosecution is pending and on the approval of the composition of the offence being given, the person against whom the offence is so compounded, shall be discharged."

The motion was adopted.

Clause 10, as amended, was added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up clause 11 of the Bill. There is one amendment by Shri Husain Dalwai. Mr. Dalwai, are you moving?

SHRI HUSAIN DALWAI: No, Sir, I am not moving.

Clause 11 was added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up clause 12 of the Bill. There are two amendments (No.19) by Shri Husain Dalwai and (No. 11) by Shri Bandaru Dattatreya.

CLAUSE – 12 AMENDMENT OF SECTION 18

SHRI HUSAIN DALWAI: Sir, I beg to move:

(19) That in the List of Amendments dated the 15th July, 2016, amendment No. 11, *after* sub-clause (h), the following be *inserted*, namely:-

"(i) the manner of recording details of offenders including first time offenders, repeat offenders, parents and guardians and means to update such details regularly.''

The question was put and the motion was negatived.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Bandaru Dattatreya, are you moving?

SHRI BANDARU DATTATREYA: Sir, I beg to move:

(11) That at page 3, *for* lines 26 to 30, the following be *substituted*, namely:-

"12. In section 18 of the principal Act, in sub-section (2):- Amendment of section 18.

(i) clause (a) shall be relettered as clause (b) thereof and before clause (b), as so relettered, the following clause shall be inserted, namely:-

"(a) the conditions and the safety measures under clause (b) of sub-section (2) and other activities under clause (b) to *Explanation* of sub-section (2) of section 3;"

(ii) in clause (b), as so relettered, *for* the words "Child Labour Technical Advisory Committee", the words "Technical Advisory Committee" shall be *substituted*;

(iii) clauses (b), (c) and (d) shall be relettered as clauses (c), (d) and (e) thereof and in clause (c) as so relettered, for the word "child", the word "adolescent" shall be *substituted*;

(iv) after clause (e), as so relettered, the following clauses shall be inserted, namely:-

"(f) the manner of payment of amount to the child or adolescent under sub-section (4) of section 14B;

(g) the manner of composition of the offence and payment of amount to the appropriate Government under sub-section (1) of section 14D;

(h) the powers to be exercised and the duties to be performed by the officer specified and the local limits within which such powers or duties shall be carried out under section 17A."

The question was put and the motion was adopted.

Clause 12, as amended, was added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up Clause 13 of the Bill. There is one amendment (No.20) by Shri Husain Dalwai. Are you moving?

SHRI HUSAIN DALWAI: Sir, I am not moving.

Clause 13 was added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I shall now take up Clause 1 of the Bill. There is one amendment (No.2) by Shri Bandaru Dattatreya. Are you moving?

CLAUSE-1 SHORT TITLE AND COMMENCEMENT

SHRI BANDARU DATTATREYA: Sir, I beg to move:

(2) That at page 1, line 3, *for* the figure "2012", the figure "2016" be *substituted*.

The question was put and the motion was adopted.

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I shall now take up the Enacting Formula of the Bill. There is one amendment (No.1) by Shri Bandaru Dattatreya.

ENACTING FORMULA

SHRI BANDARU DATTATREYA: Sir, I beg to move:

(1) That at page 1, line 1, *for* the word "Sixty-third", the word "Sixty-seventh" be *substituted*.

The question was put and the motion was adopted.

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

The Title was added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri Bandaru Dattatreya to move that the Bill as amended be passed.

SHRI BANDARU DATTATREYA: Sir, I beg to move:

''That the Bill, as amended, be passed''.

The question was put and the motion was adopted.

The Compensatory Afforestation Fund Bill, 2016

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, the next is Compensatory Afforestation Fund Bill, 2016. What do we do? ...(*Interruptions*)...

SHRI ANAND SHARMA: Sir, it is already 7 o'clock. ...(*Interruptions*)...

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: No, Sir. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. It is 7 o'clock. ...(*Interruptions*)... I will do one thing. ...(*Interruptions*)... Shri Anil Madhav Dave can move and then. ...(*Interruptions*).. He will only move and then we will ...(*Interruptions*)... You can move. ...(*Interruptions*)...

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE (SHRI ANIL MADHAV DAVE): Sir, I move:

> "That the Bill to provide for the establishment of funds under the public accounts of India and the public accounts of each State and crediting thereto the monies received from the user agencies towards compensatory afforestation, additional compensatory afforestation, penal compensatory afforestation, net present value and all other amounts recovered from such agencies under the Forest (Conservation) Act, 1980; constitution of an authority at national level and at each of the State and Union Territory Administration for administration of the funds and to utilise the monies so collected for undertaking artificial regeneration (plantations), assisted natural regeneration, protection of forests, forest related infrastructure development, Green India Programme, wildlife protection and other related activities and for matters connected therewith or incidental thereto, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration".

The question was proposed.

...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Have you moved the Bill? ...(*Interruptions*)..

SHRI ANIL MADHAV DAVE: Yes, Sir. ...(*Interruptions*)..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. That is all. ...(*Interruptions*)..